हमारे डिजीटल प्लेटफार्म
www.scgnews.in
scgnews
Social Channel Group
YouTube

RNI NO. CHHHIN/2023/87466

लाईफ वर्सिटी

मासिक

लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि उनमें से अधिकांश यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें

वर्ष : 2 | अंक : 01 | माह : जून 2024 | पृष्ठ : 8 | संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, 8817194979 | मूल्य : 5 रू.

उत्तर-दक्षिण साधने की तैयारी

माँ और भाई-बहन की तिकड़ी

हुआ तो गलत नहीं होगा. सोनिया गांधी 1999 में अमेठी और बेल्लारी से चुनाव लड़ी थीं, लेकिन बेल्लारी में चुनाव पहले हुआ था, दोनों सीट जीतने के बाद सोनिया गांधी ने तब बेल्लारी की सीट छोड़ दी थी. अब मां सोनिया गांधी के बाद प्रियंका का भी राजनीतिक डेब्यू भी वायनाड से होने जा रहा है.

2024 की लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी दो लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होते है . जिसमे से एक सीट उन्हें छोडनी थी . अब यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी वायनाड की जगह यूपी की रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे और इस सीट से अब उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़कर लोकतंत्र के मंदिर में जाने की तैयारी करेंगी . आपके जेहन में ये सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर राहुल गांधी ने उस वायनाड को क्यों छोड़ दिया जो जीत की गारंटी देता है . एक बात को समझिये, भारत की राजनीति में यूपी का महत्व सीटों की संख्या से ज्यादा है. यहां पर जीत और हार का सीधा मतलब है कि आप सियासी जगत में कितनी ताकत रखते हैं. आपको याद होगा कि 2019 के नतीजों के बाद भी विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आवाजा उठाता था. लेकिन 2024 के नतीजे के बाद विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास संख्या है. हम विपक्ष की मजबूत आवाज हैं और वो कैसे संभव हो सका क्योंकि इस दफा यूपी से इंडी ब्लॉक 43 सीटें जीतने में कामयाब हुआ है जिसमे से 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है. अब यदि कांग्रेस को यूपी में और मजबूती देनी है तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और पार्टी के रणनीतिकार यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय वो यूपी को दे सकें. राहुल गांधी द्वारा रायबरेली सीट अपने पास रखने की सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस को यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन पाने की उम्मीद . 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक सीट रायबरेली को अपने कब्जे में रख पायी थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के गठबंधन का फायदा मिला . उससे भी बड़ी बात यह हुई कि बीएसपी के वोट शेयर में जो गिरावट हुई है उसका कुछ हिस्सा कांग्रेस की झोली में गए. बीएसपी का वोट शेयर 19 फीसद से घटकर 9 फीसद हो गया. ऐसा माना जा रहा है कि 10 फीसद वोट शेयर में कांग्रेस को करीब 2 से 3 फीसद वोट मिले थे. वायनाड छोड़ रायबरेली आने के पीछे की एक वजह यह भी होगी कि हिंदी बेल्ट में जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होती है उसे केंद्र की सत्ता से दूर रहना होगा. अगर आप राजस्थान, हरियाणा के नतीजों को देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है. इस वजह से भी वायनाड छोड़ राहुल गांधी ने रायबरेली का चुनाव किया. अब इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है वो तो देखने वाली बात होगी.

गांधी परिवार का सियासी जुड़ाव भले ही उत्तर से ज्यादा रहा है, लेकिन दक्षिण कई बार उनके लिए राजीनीतिक हनुमान बनकर आया है. गांधी परिवार का इतिहास अगर देखें तो 1978 का उपचुनाव इंदिरा गांधी ने कर्नाटक के चिकमगलूर से जीतीं और फिर 1980 में तब के आंध प्रदेश के मेडक सीट ने भी इंदिरा गांधी को सांसद बनाया . अगर कहें कि 1999 में सोनिया गांधी का राजनीतिक डेब्यू भी दक्षिण भारत से

रायबरेली संग राहुल के नाता जोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक यूपी में कांग्रेस का पुनर्जीवन नहीं होगा. बात बनने वाली नहीं हैं. देश की 80 लोकसभा सीट यहां से आती हैं. उससे भी बड़ी बात यह है कि यूपी में जीत का मनोवैज्ञानिक फायदा होता है. आपको 4 जून की वो तारीख याद भी होगी जब राहुल गांधी ने कहा था कि वैसे तो विपक्ष की जीत में देश के हर सूबों ने जमकर सहयोग दिया है. लेकिन वो यूपी की जनता को स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे जिन्होंने संविधान पर हमले को समझा था. इस तरह से राहुल गांधी ने हिंदी बेल्ट को साधने की कोशिश की. वहीं वायनाड में प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाकर दक्षिण भारत को भी साधने की कोशिश करेंगे.

2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित कांग्रेस ने अपना रुख बदल रही है. राहुल गांधी का रायबरेली संसदीय सीट को बरकरार रखना और वायनाड सीट छोड़ना उसकी रक्षात्मक की जगह आक्रामक रुख का संकेत है. वायनाड रखते तो यह राहुल गांधी के एक रक्षात्मक दृष्टिकोण दिखलाता, क्योंकि राहुल 2019 में अमेठी से अपनी संभावित हार को देखते हुए वहां पहुंचे थे. उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव नीतजों के देखकर ही राहुल ने वायनाड के बजाय रायबरेली को चुना है%. अब तक राहुल गांधी वायनाड के सांसद के रूप में दक्षिण और प्रियंका उत्तर की कमान संभाल रही थीं, जो कांग्रेस की पुरानी रणनीति थी. इस बार के लोकसभा चुनाव परिणाम महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस को एक उम्मीद जगी है और इसके परिणामस्वरूप उसकी रणनीति में बदलाव आया है. कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि भाजपा को चुनौती देनी है तो लड़ाई वहां लड़नी होगी जहां भगवा पार्टी वह मजबूत है. बीजेपी हिंदी बेल्ट में काफी मजबूत है. दक्षिण में वह अब भी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है. प्रियंका गांधी के वायनाड जाने से केरल भी सध जाएगा जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होंने वाले है . भाई राहुल की जगह प्रियंका गांधी के वायनाड से चुने जाने पर राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कैम्पेन को भी गति मिलेगी.

स्वतंत्र भारत के राजनीतिक गलियारे में झांके तो अब तक गांधी परिवार से जवाहर लाल नेहरू , इंदिर गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी , मेनका गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी और अब यदि प्रियंका गांधी वायनाड जीत जाती है तो संसद में गांधी परिवार के एक और सदस्य का नाम दर्ज हो जायेगा .लेकिन इस बीच एक अलग बात यह है कि इस बार गांधी परिवार का कोई भी सदस्य सत्ता पक्ष से संसद में नहीं रहेगा और दूसरी ओर अगर प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीत जाती हैं तो पहली बार ऐसा होगा जब माँ और भाई-बहन की तिकड़ी संसद में मौजूद रहेगी विपक्ष की आवाज बनकर .

आरएसएस हटी भाजपा की सीट घटी

10 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन पर कहा कि जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर्यादा की सीमाओं का पालन करता है अपने काम पर गर्व करता है अहंकार से रहित होता है ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में सेवक कहलने का हकदार है काम करें लेकिन मैंने किया यह अहंकार न पाले. यह बात उन्होंने पॉलीटिकल पार्टी के अब हो रहे रवैये पर बोल रहे थे, अहंकार वाली बात किसके लिए कही या उनका इशारा किसकी ओर था यह साफ तो नहीं है लेकिन लोग अपने-अपने हिसाब से कयास जरूर लगा रहे हैं. लोकसभा चुनाव में चौथे राउंड की वोटिंग के बाद भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा का यह कहना की शुरुआत में जब हम कम सक्षम थे तब हमें ह्यह्य की जरूरत पड़ती थी आप हम सक्षम है आज बीजेपी खुद अपने आप को चलती है

इन सब से एक बात तो साफ हो रही है कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में खींचतान चल रही है. वैसे यह खींचतान बीते तीन-चार साल से चल रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नजर रखने वाले और उस पर एनालिसिस करने वाले लोगों का मानना हैं कि भाजपा ने चुनाव के दौरान आरएसएस की सलाह को लगातार नजरअंदाज करती रही है दावों में यह भी कहा गया है कि आरएसएस वर्कर से कहा गया था कि वें प्रचार से दूर रहे क्योंकि उनके रहते माइनॉरिटी के वोट मिलना मुश्किल होता है.

आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में खींचतान चल रही है. वैसे यह खींचतान बीते तीन-चार साल से चल रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नजर रखने वाले और उस पर एनालिसिस करने वाले लोगों का मानना हैं कि भाजपा ने चुनाव के दौरान आरएसएस की सलाह को लगातार नजरअंदाज करती रही है दावों में यह भी कहा गया है कि आरएसएस वर्कर से कहा गया था कि वें प्रचार से दूर रहे क्योंकि उनके रहते माइनॉरिटी के वोट मिलना मुश्किल होता है.

तो प्रश्न यह उठता है, क्या आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं थी. आरएसएस से जुड़े मेरे मित्र कहते हैं कि आरएसएस किसी के साथ नहीं होती वह सिर्फ एडोलॉजी के साथ होती है.बीजेपी चुनाव में आरएसएस की आईडियोलॉजी के साथ नहीं थी.बीजेपी पीछे हटी आरएसएस नहीं हटी थी.

इससे एक बात तो साफ होती है जिसकी चर्चा लगातार बनी हुई है आरएसएस के कार्यकर्ता चुनाव में बीजेपी के लिए माहौल बनाने और विपक्ष का नेरीटिव तोड़ने में एक्टिव नहीं रहे.

सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने राम मंदिर बनने के बाद से आरएसएस की बात सुनना बंद कर दिया था उसने आरएसएस की सलाह पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा.कहा जाता है कि भाजपा ने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष पीएम मोदी के करीबी निर्पेंद्र मिश्र को बनाया था. मिश्रा वही है जिन्होंने 2014- 2019 में पीएमओ के सबसे खास अधिकारी हुआ करते थे और राम मंदिर आंदोलन के वक्त वह यूपी में (शेष पृष्ठ 2 पर)

विदेशों में डंका, भारत में शंका

भारत की तरह ही दक्षिण अफ्रीका ने भी इतिहास लिख दिया है। वहाँ सम्पन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त सीरिल रामफोसा को दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर से अपना राष्ट्रपति चुना है। इससे दक्षिण अफ्रीका समेत ग्लोबल साउथ के देशों में भारत की स्थिति और अधिक मजबूत होनी तय मानी जा रही है। भारत जी-20 से ही ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। पीएम मोदी ने इटली में चल रहे जी7 में भी ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई है।

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में दो सप्ताह पहले हुए आम चुनावों में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 40 प्रतिशत मत हासिल हुए इसके बावजूद देश की संसद ने पांच साल के एक और कार्यकाल के लिए सिरिल रामफोसा को राष्ट्रपति चुन लिया है।

उन्हें शुक्रवार आधी रात राष्ट्रपति चुना गया । इससे पहले शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू हुए सत्र में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन, बार-बार व्यवधान तथा लंबी मतदान प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। एएनसी ने डीए, इंकाथा फ्रीडम पार्टी (आईएफपी) और पैट्रियटिक फ्रंट (ओएफ) के साथ गठबंधन किया है। कुछ लोगों ने इस गठबंधन को दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में एक नए युग के रूप में स्वागत किया जो सुलह का एक मजबूत संदेश देगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हालांकि, कई लोगों ने कहा कि एएनसी ने डीए के साथ गठबंधन करके देश के नागरिकों को धोखा दिया है। डीए पहले विपक्ष में था तथा उसने 1994 में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में एएनसी के पहली बार सत्ता में आने के बाद से ही उसकी नीतियों का विरोध किया है।

इधर देश में राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार को लोकसभा चुनाव में अहंकार की वजह से बीजेपी के खराब प्रदर्शन वाले अपने बयान पर यू टर्न लेना पड़ा है। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की कम सीटें आने को अहंकार का नतीजा बताया था। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि जो लोग राम की पूजा करते थे। उनको बड़ा गुरूर आ गया था। इसीलिए भगवान राम ने उन्हें दंड दिया है। उनको बहुमत नहीं मिला। इंद्रेश कुमार के इस बयान पर बीजेपी के अंदर सियासी तूफान खड़ा हो गया था। विरोधियों ने भी बीजेपी पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले दस साल से आरएसएस खुद सत्ता के मजे लूट रहा था। अब जब चुनाव के नतीजों से झटका लगा तो उन्हें अहंकार की याद आई है। संजय राउत ने कहा कि पिछले दस साल (शेष पृष्ठ 2 पर)

अबकी बार लगाम के साथ मोदी सरकार

आपन सोचा होइ नहीं, प्रभु सोचा तत्काल -

मित्रो सच ही है हम चाहे कितना भी बढ़िया सोच ले पर होगा वही जो ईश्वर की कृपा होगी जो प्रभु चाहते हैं. लोकतंत्र में जनता को ही जनार्दन कहा गया है जनार्दन यानी ईश्वर... प्रभु. नेता चाहे कितना भी सोच ले अपने हिसाब से बेहतर करने की पर होगा वही जो जनता चाहेगी . इस चुनाव में भी जनता जनार्दन ने अपना निर्णय दे दिया. अब देखिए ना चुनाव घोषित होने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, बिना रुके बिना थके. शायद उनका उद्देश्य यही रहा होगा कि अब जो तीसरी बार सरकार आएगी वह और मजबूत सरकार होगी ताकि जो भी देश हित में फैसला लेने का उन्होंने सोच रखा था ,जो काम उन्हें करने थे उसे निर्विवाद रूप से पूरा किया जा सके. लेकिन लगता है कि जनता को कुछ और ही मंजूर था. जो मेहनत प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान की थी कि अब पूरे 5 साल भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार चलेगी वह जनता जनार्दन के आदेश अनुसार गठबंधन सरकार में परिणीति हो गई. अब जब गठबंधन सरकार बन रही है तो इसमें अक्सर ऐसा होगा यह की कभी किसी सहयोगी दल को कोई आपत्ति होगी तो कभी किसी सहयोगी दल को किसी और चीज की समस्या, सभी दलों की एक-एक आपत्ति और समस्याओं को हल करते हुए सरकार चलाना होगा हालांकि प्रधानमंत्री को गठबंधन सरकार चलाने में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं होगी क्योंकि उनके दो बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है लेकिन तकलीफ एक बात की जरूर होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी गठबंधन सरकार चलाने का पूर्व अनुभव नहीं रहा है .12 वर्षों तक वह जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो या 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री , भारतीय जनता पार्टी इन सभी जगह पर पूर्ण बहुमत के साथ रही है इसलिए इन्हें मान मनौवल करना आया ही नहीं और यह जो निर्णय लेते रहे वे बोल्डली लेते रहे है और उन डिसिजनों को उनके सहयोगियों को मानना पड़ता था. उदाहरण के लिए आप कश्मीर से 370 हटाने की बात करें या किसान आंदोलन को दबाने की बात .अब बात करते हैं इनके दो प्रमुख सहयोगियों की वे है नीतीश कुमार बिहार से और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू. निश्चित तौर पर यह दोनों नेता अपने राज्यों में विकास चाहते हैं और विकास कार्यों के लिए इन्हें तो केंद्र पर ही निर्भर होना पड़ेगा. बिहार में तो अगले वर्ष ही विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पूर्व नीतीश अपने राज्य में विकास की कई नई योजनाओं को लाना चाहते होंगे जो जनहित के हो, जिससे उनकी सरकार की छवि बनती हो, इसके लिए कदम कदम पर उन्हें प्रधानमंत्री के सहयोग की आवश्यकता होगी इसलिए किसी के पलटी करने के फिलहाल कोई गुंजाइश यहां नज़र नहीं आती है. मुझे लगता है कि सरकार अभी तो निर्विवाद रूप से चलती रहेगी. हां प्रश्न उठेगा की फिर उन मुद्दों का क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पहले से ही तय कर रखे हैं. निश्चित रूप से वह सब काम उस गति से तो नहीं चल पाएंगे जो भाजपा सरकार ने सोच रखी थी . कुछ कामों में देरी होगी. हो सकता है कि कुछ कार्य कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डालना पद जाय . लेकिन इतना तो तय है कि लोक कल्याण के काम अच्छे से होते रहेंगे और इनमें (शेष पृष्ठ 2 पर)

कश्मीर से 370 हटाने की बात करें या किसान आंदोलन को दबाने की बात .अब बात करते हैं इनके दो प्रमुख सहयोगियों की वे है नीतीश कुमार बिहार से और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू. निश्चित तौर पर यह दोनों नेता अपने राज्यों में विकास चाहते हैं और विकास कार्यों के लिए इन्हें तो केंद्र पर ही निर्भर होना पड़ेगा. बिहार में तो अगले वर्ष ही विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पूर्व नीतीश अपने राज्य में विकास की कई नई योजनाओं को लाना चाहते होंगे जो जनहित के हो,

बृजमोहन की जगह कौन ?

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े और कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल जो कि रायपुर दक्षिण से विधायक रहे हैं अब रायपुर के सांसद हो गए हैं राज्य में अगले वर्ष के अंत तक नगरी निकाय चुनाव होने हैं संभावना है कि उसके साथ ही विधानसभा का उपचुनाव भी हो सकता है ऐसे में यदि बृजमोहन अग्रवाल अपने विधायक पर से इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की नेता बड़ी संख्या में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं. भाजपा में भी दावेदारों की कमी नहीं होगी रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल का एक क्षेत्र राज रहा है इसलिए उनके रहते यहां से किसी और को कभी भी भाजपा से टिकट मिला ही नहीं अब उनके सांसद बनने के पश्चात यहां पर किसी नई उम्मीदवार की तलाश होगी. छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल का एक छत्र राज रहा है अब पहली बार उनके सांसद बनने के कारण इस सीट से थोक में दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं. खबर है यह कुछ भाजपा नेताओं ने तो संत कार्यालय के चक्कर लगाने भी शुरू कर दिए हैं.

लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के दबदबे वाली सीट पर संभवत पार्टी को उनकी नजरअंदाजी अच्छी. ऐसा माना जा रहा है की सीट से किसी को टिकट देने से पहले पार्टी बृजमोहन अग्रवाल से भी उनकी मंशा जरुर पूछेगी या उनकी पसंद का प्रत्याशी को मैदान में उतर जाए क्योंकि जीतने की जिम्मेदारी तो बृजमोहन अग्रवाल की ही होगी. कुछ प्रमुख नाम जो खबरों में है उनमें से एक है सुनील सोनी जो पूर्व सांसद रह चुके हैं और पूर्व महापौर भी शहर के लोगों से कनेक्ट रहने वाले सुनील सोनी को बृजमोहन अग्रवाल का करीबी भी माना जाता है. शहर में भारतीय जनता पार्टी में सेकंड लाइन के नेताओं में सबसे सीनियर रायपुर निगम रायपुर नगर निगम के सीनियर पार्षद बृजमोहन अग्रवाल के सियासी टीम के अहम हिस्सा सुभाष तिवारी का नाम भी जोरों से लिया जा रहा है. तो बृजमोहन अग्रवाल के हमेशा गुड बुक्स में रहने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता केदार गुप्ता भी पीछे नहीं है व्यापारिक वर्ग में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है जो दो बार रायपुर उत्तर से टिकट दिए जाने की चर्चा रही लेकिन बात नहीं बन सकी थी. निगम चुनाव में कई भाजपा नेताओं को तीन बार निर्दलीय पार्षद के रूप में हरा चुके शहर दक्षिण के सुंदरलाल शर्मा वार्ड से आने वाले मृत्युंजय दुबे का नाम भी चल रहा है जो अब भाजपा में सक्रिय है तो रायपुर नगर निगम में उप नेता प्रतिपक्ष लगातार विधायक का चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे मनोज वर्मा भी सिर्फ नेताओं के संपर्क में है

यह बात केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है ऐसा नहीं है कांग्रेस ने भी दावेदारों की लंबी लिस्ट है। यह सीट कांग्रेस के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार बृजमोहन बतौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं होंगे। बृजमोहन को जननेता माना जाता है। सियासी जानकार बताते हैं की सीट पर बड़ी संख्या में लोग बृजमोहन के चेहरे पर ही वोट करते आए हैं। बृजमोहन के दिल्ली जाने से कांग्रेस के लिए यह सीट थोड़ी आसान हो सकती है इसलिए इस बार कांग्रेस का हर नेता मैदान पर उतरने की कोशिश जरूर करेगा. पूर्व में बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ किरणमयी नायक, कन्हैयालाल अग्रवाल और प्रमोद दुबे अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. पिछले चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल ने दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास को हराया था. अब आगे देखना होगा कि बृजमोहन अग्रवाल के डायरेक्ट चुनाव न लड़ने पर इस सीट पर क्या होंगे चुनावी समीकरण और क्या आएगा रिजल्ट.

लड़के लापरवाह क्यों होते हैं?

कल एक कैफे में बैठा मैं कुछ लोगों की चर्चा सुन रहा था वह कह रहे थे कि आजकल के लड़के कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो गए हैंवो एग्रेसिव हो रहे हैं उनमें केयरिंग है, वे किसी भी बात की परवाह नहीं करते. ऐसी शिकायते तो आपके पास भी होगी.जी बिलकुल सही आप जैसे ही प्रश्न मेरे दिमाग में अब क्या प्रश्न घूमने लगे और मैं सोचने लगा क्या वाकई हम पुरुष या हमारे लड़के इतने वायलेट इतने एग्रेसिव और अनकेयरिंग क्यों है ?क्या उनके डीएनए में यह चीज इनबिल्ट कर दी गई है? मुझे जवाब मिला नहीं एक्चुअली हम ही उन्हें ऐसा सीख रहे हैं हम उन्हें ऐसा बना रहे हैं. क्या यही रोल मॉडल हमने उनके सामने पेश नहीं कर रहें है.

हो सकता है आप मेरी इस बात से अभी सहमत न हों लेकिन जरा गौर करिए आजकल के हमारे टीवी,सिनेमा में या मूवी में दिखाई जा रहे पॉपुलर मेल कैरक्टर को, क्या ये मेल स्टीरियोटाइप को बढ़ावानहीं दे रहे हैं.वेभी तो एग्रेसिव है, किसी की केयर नहीं करते, पेरेंट्स की बात नहीं सुनते,सिगरेट ड्रग्स शराब जैसी चीजों में इंवॉल्व होते हैं. हमारे लड़के यही सब देखकर और सीख कर तो बड़े हो रहे हैं टीवी में,मूवी में दिखाया जा रहा है कि स्कूल में, फुटबॉल टीम में,घर-मोहल्ले में,पब्लिक में जो लड़के वायलेंट एक्टिविटीज में इंवॉल्व रहते हैं, जो प्लेबॉय टाइप के होते हैं जो बहुत सारी लड़कियों के साथ चीट करते हैं उन पर ही सबसे खूबसूरत लड़कियां फ़िदा हो जाती है प्यार करती है. ऐसे लोगों पर वो मर मिटती है.

टेलीविजन और सिनेमा का पर्दा हमारे लड़कों को इसी तरह पोर्ट्रेट कर रहा है और कच्ची उम्र से लेकर टीनएज और फिर एडल्ट होने तक लड़के यही सब देखकर बड़े हो रहे हैं इसी से सीख रहे हैं टीवी और सिनेमा हमारे लड़कों को मैसेज दे रहा है कि लड़के ऐसे ही होते हैं यही आइडियल मैनहुड है. दरअसल हमारे टीवी सिनेमा और विज्ञापन बनाने वाली कंपनियां महिलाओं का वस्तुकरण यानि मैटेलाइजेशन कर रही है. कैसे उनकी एक सेक्सुअल इमेज हर जगह पेश की जा रही है जो वास्तविकता से कोसो दूर होती है. दुर्भाग्य है कि इस विषय पर कभी कोई स्टडी नहीं होती की पॉपुलर मीडिया कैसे लड़कों की भी एक खास तरह की टॉक्सिक इमेज पेश कर रहा है सिर्फ एडल्ट कंटेंट में ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों और टीनएजर्स के लिए बनाये जा रहा है कंटेंट में भी...हमने कभी नहीं सोचा की लड़कियों की सेक्सी इमेज की तरह टीवी और सिनेमा लड़कों की भी एक खास तरह की टॉक्सिक इमेज को बढ़ावा दे रहा है हमने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि रुपए पहले पर्दे की

कहानी हमारे लड़कों और पुरुषों को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है और यह कितना खतरनाक हो सकता है. बुनियादी बात समझने के लिए है कि चाहे लड़का हो या लड़की कोई भी कमजोर, टॉक्सिक या एग्रेसिव पैदा नहीं होता परिवार, समाज, संस्कृति और पित्र सत्ता मिलकर उसे गढ़ते हैँ. दुख की बात यह है कि पितृ सत्ता ने जितना नुकसान लड़कियों को पहुंचा है उतना ही लड़कों को, फिर भी लड़कों को लगता है की पैट्रिआर्की उनके हाथ में है.हमारे देश में आज जो भी लड़के बड़े हो रहे हैं वे कच्ची मिट्टी की तरह है. वो कैसे इंसान बनेंगे, कैसे पुरुष बनेंगे यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसा बनाएंगे हम कौन सा रोल मॉडल उनके सामने पेश करते हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी इस जिम्मेदारी को ढंग से निभा रहे हैं सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ. विचार जरुर करियेगा और मुझे लिख भेजिएगा.

बचपन और टीनएज उम्र का वो पड़ाव होते हैं, जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं।

आज के दौर में कम उम्र के बच्चों में भी स्कूल, पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाने लगा है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं।

यह बेहद चिंताजनक स्थिति है क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखते रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो यह बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान ना मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आप को बच्चों में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बताते हैं। एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी तक बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल एडल्ट्स में जो मानसिक समस्याएं देखी जाती हैं वह बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बढ़ा हुआ रूप कहा जा सकता है।

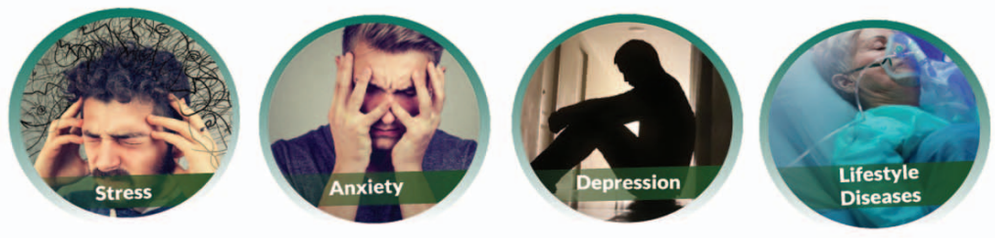

प्रथम पृष्ठ का शेष

आरएसएस हटी भाजपा की सीट घटी

प्रमुख सचिव के पद पर थे जिन्होंने कार्य सेवकों पर गोलियां चलवाई थी नृपेंद्र मिश्रा का राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया जाना आरएसएस के कई पदाधिकारी को पसंद नहीं आया था. यह बात आरएसएस ने बीजेपी के नेताओं से भी कही थी लेकिन बीजेपी ने अपना फैसला नहीं बदला और आरएसएस एवं भाजपा के बीच की खाई बनने की सबसे ठोस वजह बन गई.

दूसरी वजह थी रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर. आरएसएस चाहता था कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति से बचना चाहिए यह हिंदुत्व का मुद्दा है लोगों की आस्था का सवाल है अगर जनता को लगा कि राम मंदिर पर राजनीति हो रही है तो बीजेपी से दूर हो जाएगी आरएसएस की. इस सलाह को भी बीजेपी ने नहीं माना और इसका असर यह हुआ कि बीजेपी अयोध्या की सीट तक गंवा दी.

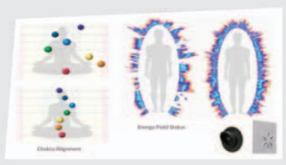

मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मामले में भी आरएसएस चाहता था कि सभी शंकराचार्य और धर्मगुरु इस आयोजन में शामिल किया उन्हें पर्याप्त तवज्जो दी जाना चाहिए पर भाजपा हर बार की तरह यह बात मानना भी जरूरी नहीं समझा. जो नाराज थे उन्हें नाराज रहने दिया उन्हें मनाना भी उचित नहीं समझा.बीजेपी ने अपने गेस्ट बुलाए जो ग्लैमर और बिजनेस की दुनिया में से थे. आरएसएस चाहता था कि संयोजन में ग्लैमर का तड़का ना लगे जबकि भाजपा ने कई बॉलीवुड स्टार्स को ऑफिशियल निमंत्रण दिया था. आरएसएस चाहता था कि रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा को पवित्र मौका मनाया जाए लेकिन यह मौका पवित्रता की जगह ग्लैमरस ज्यादा हो गया था. आरएसएस आयोजन में उन लोगों को बुलाना चाहता था जिन्होंने राम मंदिर से जुड़ा कोई संकल्प लिया हो कोई शपथ ली हो की मंदिर बनने तक चप्पल और पगड़ी नहीं पहनेने जैसा संकल्प. अयोध्या के आसपास कुछ राजपूत समुदाय है जिन्होंने मंदिर बनने तक पगड़ी नहीं पहनने का संकल्प लिया था यह आरएसएस की लिस्ट में शामिल थीं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तरजीह नहीं दी.

प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद पूजा करने का जो फैसला लिया था,उससे भी आरएसएस सहमत नहीं था. अरएसस चाहता था कि यह जिम्मेदारी किसी बड़े धर्मगुरु संत या फिर लालकृष्ण आडवाणी को दी जाए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई की थी पर यह भी नहीं हुआ और तो और आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले आडवाणी और मुरली मनोहर जैसी नेताओं को किनारे करने की कोशिश भी हुई. आरएसएस ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल का चुनाव में उपयोग के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देता रहा है. आरएसएस मानता था कि इससे विपक्ष की विक्टिम जैसी छवि बन रही है जिसे विपक्ष को फायदा मिल रहा है और ग्राउंड पर हमारे कार्यकर्ता इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं वह डिफेंसीव हो रहे हैं पर भाजपा ने इसे भी इग्नोर किया. बीजेपी जिस तरह दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने यहां शामिल कर रही थी जिन पर करप्शन से आरोप लगे थे उसको लेकर के भी पार्टी को चेतावनी दी थी आरएसएस ने चेताया था कि जमीनी स्तर पर इसके सरकार की छवि और भाजपा की छवि बिगाड़ रही है लेकिन यह सब भी भाजपा ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी.

यूपी से जुड़े कुछ मेरे आरएसएस के मित्र कहते हैं कि इस चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा है उसे आरएसएस ने टिकट के बंटवारे के वक्त ही भाँप लिया था . आरएसएस का मानना था कि कुछ सांसदों को छोड़कर नए लोग को टिकट देना चाहिए जैसा दिल्ली में किया गया था लेकिन यहां भी आरएसएस की नहीं चली . लोग कहते हैं कि मोदी सरकार के नारे से भी आरएसएस नाराज था यह यह नारा आरएसएस के आईडियोलॉजी में फिट नहीं बैठता. क्योंकि आरएसएस हमेशा संगठन या समूह को तरजीह देता है ना कि किसी व्यक्ति विशेष को और मोदी सरकार के नारे से एक व्यक्ति सर्वोपरि दिखाई दे रहा था. अब इस पर चर्चा हो रही है कि क्या चुनाव में मोदी को सर्वोपरि मानना एक बड़ी गलती थी.

उड़ीसा के बारे पर वह कहते हैं कि यहां की जीत पर बीजेपी को कम नहीं बांधना चाहिए उड़ीसा के लोग नवीन पटनायक की बीमारी और ब्यूरो क्रेसी के हाथों में जा रही सत्ता से नाराज थे उनके सामने कांग्रेस का विकल्प नहीं था सामने सिर्फ बीजेपी थी अगर कांग्रेस जोर लगती तो नतीजा ऐसा बिल्कुल नहीं होता. कुल मिलाकर कहें तो अब गेंद बीजेपी के पाले में है यदि बीजेपी इन चीजों पर रिव्यू नहीं करती है तो तो 2029 का चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा. भाजपा को अब समझना होगा कि गठबंधन की सरकार चलाने के लिए लचीला होना होगा. यह मोदी की सरकार नहीं गठबंधन की सरकार है. पूर्व में भी भाजपा की सरकार थी किसी और की सरकार होने की गलतफहमी ना पाला जाए .

विदेशों में डंका, भारत में शंका

से बीजेपी सत्ता का दुरुपोयग करती रही है। बदले की राजनीति करती रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है। अब भी संघ को बीजेपी की गलतियां समझ में आ गई हैं, तो वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाए। इंद्रेश कुमार के बयान पर अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी उनको घेरा है। सत्येंद्र दास ने कहा कि इंद्रेश कुमार हिंदू-मुस्लिम एकता की कोशिश कर रहे थे, फिर भी इस बार चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। इंद्रेश कुमार अपने मिशन में नाकाम रहे। इसीलिए, अब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं।

इंद्रेश कुमार ने अपने बयान पर मामला बढ़ता देख इससे किनारा कर लिया और पल्ला झाड़ लिया। संघ के नेता इंद्रेश कुमार को भी अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा है। अब इंद्रेश कुमार ने कहा कि उनके कहने का बस इतना ही मतलब था कि देश में रामभक्तों की सरकार बनी है। रामविरोधी आज भी सत्ता से बाहर हैं।

बाबा रामदेव ने कहा कि, राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी, राम सबके हैं, राष्ट्र सबका है और आपस में भी हम सब एक दूसरे के हैं. उन्होंने कहा कि, किसी भी प्रकार की जाति, संप्रदाय या विचार धाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए ठीक नहीं है. रामदेव ने भरोसा जताया है कि, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और जवाब दिया. इसके अलावा उन्होंने मौजूदा सरकार से अपेक्षाओं का भी जिक्र किया और कहा कि, देश के सामने कितनी भी चुनौती क्यों न हो पीएम मोदी देश को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.

उधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्र7 के बैठक में इटली पहुँचे जहाँ उनकी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे सहित वैश्विक मंचों तथा बहुपक्षीय प्रस्तावों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। एक दिवसीय यात्रा के अंत में शुक्रवार को दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान मोदी ने त्र7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए इटली की प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय ने बैठक के बारे में जारी विज्ञप्ति में कहा कि नेताओं ने खुले एवं मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई तथा भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा की। क्षेत्र में चीन की आक्रामक गतिविधियों के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा, ''दोनों नेता मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को पूरा करने की खातिर तैयार रूपरेखा के तहत क्रियान्वित की जाने वाली संयुक्त गतिविधियों के लिए तत्पर हैं।%% इसने कहा कि उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की तथा भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे सहित वैश्विक मंचों और बहुपक्षीय प्रस्तावों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) परियोजना के तहत सऊदी अरब, भारत, अमेरिका और यूरोप के बीच एक विशाल सड़क, रेलमार्ग और पोत परिवहन तंत्र की परिकल्पना की गई है ताकि एशिया, पश्चिम एशिया और पश्चिम के बीच जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके। आईएमईसी को समान विचारधारा वाले देशों द्वारा चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव% (बीआरआई) के समक्ष रणनीतिक प्रभाव हासिल करने की पहल के रूप में भी देखा जा रहा है।

ीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली के अपुलिया में जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात बेहद खास रही। पीएम मोदी ने इस बार भारत की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार जॉर्जिया मेलोनी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इसके बाद इटली की पीएम ने भी उसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। बता दें कि जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन के दौरान पीएम मोदी ने देश में हाल में हुए लोकसभा चुनाव और उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया की तारीफ में कसीदे पढ़े। पीएम मोदी ने देश की चुनावी प्रक्रिया को पूरे लोकतांत्रिक विश्व के लिए बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि भारत का चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। जी सेवन समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि त्र7 संग उनके देश का संवाद और सहयोग जारी रहेगा।पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी में एकाधिकार को समाप्त करने का आह्वान किया और कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे रचनात्मक बनाया जाना चाहिए ।पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है।

अबकी बार लगाम के साथ मोदी सरकार

कोई अड़चन नहीं आने वाली. बरहाल नरेंद्र मोदी को ठ्ठस्त्रड्ड अलायेंस का नेता चुन लिया गया है उन लोगों ने सहयोगी दलों के साथ राष्ट्रपति भवन जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है 9 जून को नरेन्द्र मोदी पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे तब तक मंत्रिमंडल के गठन और उसमें अपनी हिस्सेदारी की सहयोगी दलों की मांगों को भी सुलझा लिया जाएगा और बहुत हद तक यह संभव है कि सब कुछ तय हो ही चुका होगा .फिर भी बहुत से लोगों को यह विश्वास नहीं आ रहा है और उनका यह मानना है कि चंद्रबाबू नायडू और खासकर नीतीश कुमार तो कभी भी पल्टी मार सकते हैं तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए की 10 निर्दलीय सांसदो ने भी ह्ख्ठ को मतलब नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया है. फिर ये मत भूलिए कि 12 सांसदो वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना भी है जो पूर्व में एनडीए के ही सहयोगी दल रहे हैं यदि भाजपा के नेता उद्धव ठाकरे को चुनाव पूर्व गठबंधन करके उन्हें मुख्यमंत्री पद ऑफर कर देते हैं तो पूरी संभावना है कि दोनों शिवसेना एक साथ आ जाए और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी एनडीए गठबंधन की सरकार को मजबूती दे देगे. देश को यह भी याद रखना चाहिए की 1991 में 235 सीटों वाली कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार पूरे पांच वर्ष चली थी जबकि नरसिम्हा राव ज्यादा लोकप्रिय नेता भी नहीं थे. मोदी के पास तो 242 सीटें हैं और वे वर्तमान में सबसे लोकप्रिय नेता भी . इसलिए 2024 में बनने वाली यह जो एनडीए की सरकार है मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार के खतरे में आने वाली है.वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं उसके पक्ष में अधिक होती है जिसके पास संख्या बल होता है. देश के मतदाताओं ने जो स्पष्ट जनादेश दिया है उसे लगता है कि मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में वह पसंद तो करते हैं लेकिन उनकी जो अधिनायक वाली सोच उनको मंजूर नहीं. क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए इसे एक चेतावनी की घंटी समझा जा सकता है ?. इस चुनाव में एक ख़ास बात रही वो ये कि कोई लूजर नहीं रहा है. सब ने कुछ ना कुछ जरूर पाया है, भाजपा को सबक मिला है तो कांग्रेस को उत्साह, सपा को उम्मीदें,चुनाव आयोग और द्ग1द्ब को दोषों -आरोपों से मुक्ति. हारा तो केवल अहंकार है.

चलते चलते गोस्वामी तुलसीदास का ये दोहा आपके नाम

नहिं कोउ अस जन्मा जग माहीं।
प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं।।
राम राम

अंतिम पृष्ठ का शेष

पहले बताया पाक साफ, अब कहते हैं गड़बड़ी हुई

एक ही सेंटर से एक ही सीरीज के 63 64 65 66 67 रैंक कैसे आ सकते हैं प्रश्न तो . कहा जाता है कि पूरे देश में ऐसे तीन सेंटर हो गए हैं जिनमें से हरियाणा राजस्थान और तेलंगाना शामिल है.

हमने इतने हाई मार्क्स ने 720 में 720 वह भी 67 स्टूडेंट . एक साथ इतना हाई मार्क्स जो आया है उसे जानने समझने हमने की कोशिश की , हमने यह भी जानने की कोशिश की जिस तरह से पीडीएफ में दिखाया जा रहा है कि किसी भी छात्र को 718 719 717 नंबर मिले हैं वह कैसे संभव हो सकता है जबकि एक प्रश्न चार नंबर का होता है और यदि गलती होती तो एक नंबर नेगेटिव मार्किंग होती है तो कायदे से या तो 720 मिलेंगे या फिर 716 715. मतलब यदि कोई छात्र एक प्रश्न को छोड़ देता है तो उसे 716 अंक मिले हैं और यदि वह छोड़ता नहीं है और एक प्रश्न गलत हो जाता है तो उसे 715 नंबर मिलेंगे. फिर 719 718 717 कैसे प्राप्त हुए. दलील मिलती है कि दरअसल एग्जाम के समय पेपर में कुछ गलतियां हो गई थी पेपर गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था जिससे अंदाजा यह लगाया गया सीसीटीवी फुटेज को देखकर के की छात्रों का लगभग 15 से 20 मिनट खराब हुआ है दूसरे पेपर को देने में. इसलिए उसे समय के दौरान जितने प्रश्न हल हो सकते थे उतने प्रश्नों पर ग्रेस मार दे दिया गया. क्या दलील है भाई अब यहां से खेल को समझिए. नीट के प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न होते हैं 180 और उनके अंक होते हैं प्रति प्रश्न पर चार यानी की 180 * 4= 720 अंकों का पूरा प्रश्न पत्र हुआ नेट के एग्जाम का और इन प्रश्नों को हल करने का समय होता है 3 घंटा 20 मिनट . इसे हम मिनट में बदल लेते हैं तो मोटा-मोटा मान लेते हैं 200 मिनट आता है सभी 180 प्रश्नों को हल करने में इसे सेकंड पर ले जाए तो यह लगभग 12000 सेकंड होता है.मतलब एक बच्चे को एक प्रश्न सॉल्व करने में अमूमन 66.6 सेकंड का समय लगता है. अब मान ले कि एनटीए के मुताबिक एक छात्र को 200 सेकंड का नुकसान हुआ होगा जो पेपर बांटने में डिले हो गया था ,दोबारा पेपर जो दिया गया था तो छात्र के पास में 10000 सेकंड बचते हैं यानी की छात्र ने लगभग डेढ़ सौ प्रश्न इस समय में सॉल्व किए होंगे. अगर हम मानलेते है की बहुत ही ब्रिलिएंट स्टूडेंट रहा होगा तो. यदि सभी सही हुई तो उसके 600 मार्क्स आए होंगे 150 * 4 = 600 मार्क्स. अब खेल समझिए क्या हुआ होगा .हुआ यह कि एनटीए ने मान लिया कि लगभग 30 सवाल बच्चों ने सॉल्व ही नहीं किए होंगे और उन सभी को सही होंगे इसलिए उन्हें 30 प्रश्नों पर ग्रेस दे दो ,तो एक प्रश्न चार नंबर का होता है 30 प्रश्न हुए तो कुल हुए 120 नंबर के जो प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सभी छात्रों के 30 के 30 प्रश्न सही हो अब इसमें हुआ यह की जो बच्चा खूब मेहनत करके 620 नंबर लाया था 716 नंबर लाया होगा 715 नंबर लाया होगा वे बच्चे और जिसने 600 नंबर ले कर आये वो सारे बच्चे बराबर हो गए यानी कुल मिलाकर के 83त्न लाने वाला बच्चा और 99 और 100त्न मार्क्स लाने वाला बच्चा अब एक केटेगरी में आगये यानी की 720 में से 720 पा गए. तब प्रश्न यह है और जरूर आपके दिमाग पर उठ रहा होगा की ये 719 ,718 ,717 कैसे आ गये भाई. तो यही तो है भैया ग्रेस का कमाल .

यार यदि कोई छात्र 180 प्रश्नों में से 151 प्रश्नों सॉल्व करता है और उनमें से एक प्रश्न गलत हो गया तो उसका जो नंबर आएगा यानी की 150 सही है तो 150*4 = 600 नंबर आएंगे अब उसमें एक हो गया गलत तो एक नंबर का नेगेटिव मार्किंग हुआ यानी 599 मार्क्स आए अब ग्रीस की यदि 120 नंबर में जोड़ देता हूं तो यह 719 हो जाते इसी तरह 718 दिया गया इसी तरह 717 दिया गया है. यह है एक स्कैन जो की सामान्य लोगों की समझ में नहीं आ रहा है इतना बड़ा खेल हो गया है .

क्या होगा उनका पहले जो बच्चे 690 मार्क्स लाकर के भी टॉपर होते थे और एम्स दिल्ली उनको मिल जाया करता था अब 690 मार्क्स के ऊपर 4420 से लेकर 5202 की रैंक भी है यानी की 690 तक 600 बच्चे हैं कितने जाएंगे एम्स में ...क्या हो रहा है , पेपर को सरल बनाकर के आपने क्या कर दिया , इसे सरल बनाया या ग्रेस के नाम पर कोई घोटाला किया जा रहा है . कुछ जानकार लोग तो उसकी इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर ही शंका बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के समय से ही इस स्कैम की शुरूआत हो गई थी ,क्योंकि कई बच्चों के नाम के आगे उनके सरनेम नहीं लगाया नहीं लगाया गया है ताकि उन बच्चों को अच्छे से आईडेंटिफाई किया जा सके और उन्हें पास किया जा सके . समझिए 650 नंबर पाने वाले बच्चों को हंड्रेड परसेंट कन्फर्म होता था कि उसे बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा , वे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे अब उनकी रैंक 30000 के आसपास आ चुकी है.

ध्यान से समझिये इस पूरे स्कैम को .. देश में प्राइवेट मेडिकल कोल्लेज के भरमार हो रही है . यहा फीस लाखो करोडो में होती है . जहां पैसो वालो के बच्चे पढ़ते है ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप अपने डाक्टर होने के सपने अपने पैसो के दम पर बच्चो के नाम से खरीदते है . य जानते है की उनके बच्चे कभी भी नीट क्कालीफाई नहीं कर पायेगे तो इस ग्रेस के तहत उनका उद्धहर हो गया . क्योंकि यदि 100 नम्बर भी ग्रेस मिला और उनका बच्चा यदि 70-80 नम्बर भी ला लिया तो उसका एडमिशन किसी न किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो ही ही जाएगा . तडपेगा तो वह बच्चा जो दिन रत मेहनत करके 500 से 600 नम्बर लाया होगा . समज रहे है न कितना भयानक स्कैम हो रहा है .

सोचिये जरा उन गरीब बच्चों का जो देश के दूर-दूर गांव से आते हैं उन बच्चों का क्या होगा , क्या वे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे ? इतने नंबर लेकर के आने के बाद भी यदि उन्हें कॉलेज नहीं मिलेगा तो उनका मेंटल स्टेटस होगा ? जरा सोच करके देखिए शायद ऐसे बच्चे ही आत्महत्या कर रहे है. फिर ऐसी आत्महत्या करने वाले बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा ?

आईएएस नेता पांडियन का पराभव

संदीप साहू

मोहन चरण माझी ने ओडिशा में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, लेकिन इन चुनावों में चर्चाओं में रहे आईएएस अफसर से नेता बने वीके पांडियन की अविश्वसनीय कहानी की मिसाल भारतीय राजनीति में पहले शायद ही कभी देखी गई होगी। राजनीति में इतना छोटा कॅरिअर भी शायद ही किसी और नेता का होगा। नौकरी से इस्तीफा देने के बाद 27 नवंबर, 2023 को उन्होंने औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश किया और ओडिशा के तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) में शामिल हुए। लेकिन चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद नौ जून को उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का एलान कर डाला। उनका राजनीतिक जीवन सिर्फ 195 दिनों का रहा। सन 2000 में आईएएस बनने के बाद वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। अपनी मेहनत और लीक से हटकर काम करने की असाधारण क्षमता के कारण उन्होंने खूब प्रशंसा बटोरी। पहले मयूरभंज, फिर गंजाम जिले के कलेक्टर के रूप में उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को लोग आज भी याद करते हैं। दोनों ही जिलों में कामों के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया । ये सब थीं एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पांडियन की उपलब्धियां। लेकिन सत्ता की राजनीति में उनका प्रवेश तब हुआ, जब गंजाम के जिलाधीश के रूप में उनके काम से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें सन 2011 में अपना निजी सचिव बनाया। अपनी काबिलियत के जरिये पांडियन ने नवीन का विश्वास जीता और धीरे-धीरे अपनी काया विस्तार करने लगे।

2019 में लगातार पांचवीं बार चुनाव जीतने के बाद नवीन पटनायक ने सरकार को अधिक लोकाभिमुखी करने के लिए 5 टी (टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमलाइन) नामक एक नया विभाग खोला और पांडियन को इसका सचिव बना दिया। सरकार के सभी विभागों को इस नए विभाग के अंदर लाया गया। इसके बाद सरकार में पांडियन का दबदबा और भी बढ़ गया। पांडियन के नौकरी से इस्तीफा देने के बाद उन्हें इस विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया, ताकि सरकार में उनकी पकड़ बनी रहे। 2019 के चुनाव के बाद नवीन ने अपने निवास से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया और दल व सरकार दोनों का पूरा जिम्मा पांडियन को सौंप दिया। कोविड के बाद मुख्यमंत्री न सचिवालय गए, न विधानसभा। कैबिनेट की बैठक में भी वे वीडियो लिंक के जरिये अध्यक्षता करने लगे। अपने दल के नेता, मंत्री, विधायकों से मिलना उन्होंने लगभग बंद कर दिया। यहां तक कि राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के लिए भी सलाह-मशवरे के लिए मुख्यमंत्री से मिलना दूभर हो गया और वे पांडियन के आदेश पर काम करने लगे।

अब पांडियन की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और वह राज्य सरकार के चॉपर का इस्तेमाल कर पूरे राज्य का दौरा करने लगे। बहाना था कि लोगों से उनकी शिकायतें लेकर तत्काल कार्रवाई करना। बाद में पता चला कि पांडियन राजनीति में प्रवेश करने के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। वह जहां भी गए पूरा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेता, विधायक और मंत्री उनकी सेवा करते हुए नजर आए। मंच पर पांडियन के अलावा कोई भी देखने को नहीं मिला। साफ था कि उनकी ताजपोशी की तैयारी चल रही थी। इस बात की जमकर चर्चा हुई कि वह नवीन के उत्तराधिकारी हैं। नवीन ने ऐसी चर्चाओं का खंडन करने की कोशिश भी नहीं की, जिससे ओडिशा के लोगों में यह धारणा और भी पुख्ता होती गई कि नवीन ने पांडियन को अपना उत्तराधिकारी बनाने का मन बना लिया है। इस धारणा को तब और बल मिला, जब पांडियन ने औपचारिक रूप से बीजद में योगदान किया।

इस वर्ष मार्च में जब बीजद और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, तब बीजद की ओर से पांडियन ही इसके सूत्रधार थे। प्रेक्षकों का मानना था कि भाजपा से गठबंधन कर वह अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नवीन के डर से पार्टी के जो नेता चुप बैठे है, वे नवीन के बाद उनके खिलाफ बगावत पर उतर आएंगे, तब उन्हें भाजपा के समर्थन की जरूरत होगी। हालांकि बात बनी नहीं और भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी।

इस बार चुनाव का पूरा मोर्चा पांडियन ने संभाला। उम्मीदवारों के चयन से लेकर रणनीति तैयार करने और आर्थिक संसाधन के उपयोग से लेकर मीडिया कैंपेन तक लगभग सब कुछ उन्हीं की देखरेख में हुआ। करीब डेढ़ महीने के चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर अकेले पांडियन ही प्रचार करते नजर आए। मुख्यमंत्री और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक बीच-बीच में उनके साथ प्रचार के लिए जाते रहे, लेकिन पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों में से 38 पूरे चुनाव के दौरान नदारद रहे, और पार्टी को इसी बात का खामियाजा भुगतना पड़ा। भाजपा ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत ओड़िया अस्मिता को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी भाजपा नेता हर आमसभा में इसी बात को दोहराते रहे कि नवीन साढ़े चार करोड़ ओड़िया लोगों की अस्मिता को पैरों तले रौंदते हुए तमिलनाडु में जन्मे एक आदमी को ओडिशा के लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की यह रणनीति काम कर गई। राज्य में चौथे और अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले नवीन ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि पांडियन उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

चुनाव में हार के बाद अब तक सहमे हुए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब पांडियन को हार का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ खुलकर नारेबाजी करने लगे हैं। चुनाव खत्म होने तक हर जगह दिखाई देने वाले पांडियन परिणाम आने के बाद से कहीं नजर नहीं आ रहे। इसके बावजूद नवीन ने पांडियन को चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहराने या उनकी निंदा करने से साफ इन्कार कर दिया है। इसके उलट उन्होंने पांडियन की जमकर प्रशंसा की है और उनके खिलाफ हो रही बयानबाजी को अनुचित बताया है। नवीन के इसी आचरण और उच्चारण के कारण राजनीति से संन्यास लेने की पांडियन की घोषणा के बाद भी बहुत कम लोग यह मानने के लिए तैयार हैं कि अब राजनीति में कभी उनकी वापसी नहीं होगी। ज्यादातर प्रेक्षक मानते हैं कि पार्टी में उनके खिलाफ फैले आक्रोश के मद्देनजर यह एक टैक्टिकल रिट्रीट भर है और मामला ठंडा होने पर प्रत्यक्ष नहीं, तो परोक्ष रूप से उनकी वापसी की पूरी संभावना है।

निराधार थे लोकतंत्र पर उठे सवाल

गिरीश्वर मिश्र

विश्व के सबसे बड़े चुनाव के दौरान देश की जनता को भारतीय लोकतंत्र की चाल-ढाल की विलक्षण छटाएं देखने को मिलीं। 11 लाख और 8 लाख से अधिक के अंतर से लोग जीते तो नोटा का भी इस्तेमाल किया गया। निर्वाचन आयोग पर तोहमतें लगती रहीं, पर उसने मुस्तैदी से और निष्पक्षता से कार्य किया। संविधान, लोकतंत्र और ईवीएम पर सवाल उठे, लेकिन नतीजों ने ऐसा करने वालों को गलत साबित कर आईना दिखाया। नतीजे बता रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र को कहीं कोई खतरा नहीं। चुनावी सरगर्मी कभी नर्म-गर्म रही तो कभी तल्ख हुई। एक ओर से अतिरेक का उत्तर भी अतिरेक से ही दिया जाता रहा। ऐसे क्षण भी आए, जब शिष्टाचार की मर्यादाएं टूटती नजर आईं। इस ओर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उचित ही टिप्पणी की। निर्वाचन आयोग ने प्रचारकों को सख्त हिदायत दी और कुछ को प्रचार कार्य से अलग भी किया। सत्ताधारी दल में अति आत्मविश्वास था कि 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। उसे सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा तो मिला, लेकिन पिछली बार से कम सीटें ही मिल सकीं। मोदी काल में कई मोर्चों पर सक्रियता का ही फल है कि छह दशक पहले का इतिहास दोहराते हुए नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग लगातार तीसरी बार सरकार बना सका। कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया।

चुनाव में तमाम सवाल उठे। सनातन और राम-मंदिर निर्माण को लेकर भी अनर्गल प्रश्न उछलते रहे। विपक्षी दलों ने अपनी शक्ति-सामर्थ्य के बिंदु गिनाने में जितना श्रम किया, उससे अधिक विरोधी के छिद्रान्वेषण में लगाया। शक्ति और सामर्थ्य के नाम पर दिवास्वप्न सरीखे प्रलोभनों की यह लंबी सूची तैयार की जाती रही कि अगर सरकार बन गई तो किसे क्या-क्या दिया जाएगा। चुनाव के बीच अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक के विवाद को भी तूल दिया गया। बहुसंख्यक होने से हिंदू और हिंदुत्व को संशयग्रस्त पहचान के रूप में स्थापित करना और अल्पसंख्यक के लिए खतरे से रक्षा का नाटक अपने वोट सुरक्षित करने के लिए किया जाता रहा। यह राष्ट्र बोध और देश, संस्कृति सभ्यता सबको हाशिए पर धकेलने का उपक्रम बन गया।

हमेशा की तरह जाति को लेकर टिकट बांटने और मतदाताओं को अपने पक्ष में लेने की कोशिश सभी दलों ने की। जाति समाज की एक सच्चाई है, और सभी दल उसकी निंदा करते हैं, परंतु उसी का सहारा भी लेते हैं। चुनाव नतीजों ने जाति के बनते-बिगड़ते समीकरणों की भूमिका फिर दिखा दी। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे भी छाए रहे। इसके बाद भ ी

सबके मन में केंद्र में एक मजबूत सरकार लाने की इच्छा थी। भाजपा को इससे लाभ मिला। भाजपा दक्षिण भारत में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रही। चुनाव परिणाम जनता के विश्वासमत की पुष्टि करते हैं। परिणाम इसके परिचायक हैं कि लोकतंत्र के भविष्य को लेकर जो सवाल-संदेह उठाए जा रहे थे, वे निराधार थे। संदेह जताने वालों को जनता ने यही जवाब दिया कि यह महज एक दुष्प्रचार ही था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। करीब 64 करोड़ वोटों के आधार पर आए नतीजे ये बताते हैं कि भारतीय लोकतंत्र सबल है और उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं।

चुनावों में कई पार्टियों के दावों, वादों, आरोप-प्रत्यारोप की भाषा जमीनी वास्तविकताओं की जगह दिवास्वप्न को रेखांकित कर रही थी। इससे जनता के सामने चकित, भ्रमित और भयभीत होने की स्थितियां भी आती रहीं। लोकतंत्र के आसन्न विनाश, संविधान का समापन, आरक्षण नीति पर ग्रहण आदि से जुड़ा दुष्प्रचार तथा राजकीय तंत्र के दुरुपयोग से जुड़े आरोपों को लेकर भारत में लोकतंत्र के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगाया जाता रहा। हास्यास्पद टिप्पणियों और तर्कहीन अधकचरे प्रस्तावों के साथ कर्ज माफी, विभिन्न समुदायों को सहायता राशि की सौगातें बांटने, आरक्षण की सीमा घटाने-बढ़ाने और उसे पंथ-समुदाय की सदस्यता से जोड़ने की घोषणाओं से जनता को लुभानें के प्रयास किए जाते रहे। चूंकि मोदी सरकार ने एक दशक में जमीनी परिस्थिति को बदलने का काम किया था, इसलिए इसका सीधा अनुभव जनता को हुआ था। इस बार का जनादेश मोदी की राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता की पुष्टि करता है। अमृतकाल में विकसित भारत का संकल्प लेकर उस दिशा में अग्रसर होने को उद्यत मोदी भारत के प्रतिनिधि के रूप में अब पुन: प्रतिष्ठित हो रहे हैं। एक समर्थ, शक्तिशाली और संभावनाशील भारत की छवि को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की रीति-नीति परीक्षा की कसौटी पर कसी जाएगी। महंगाई और रोजगार के सवाल नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय अभी भी कड़ी चुनौती दे रहे हैं, जहां अतिरिक्त संसाधनों का निवेश और व्यवस्थागत परिवर्तन स्वाभाविक हो गए हैं। यदि समाज, विशेषत: युवा वर्ग स्वस्थ और सुशिक्षित नहीं होगा तो विकास के सपने अपूर्ण रह जाएंगे।

इससे इन्कार नहीं कि ये विषय अभी भी उपेक्षित हैं। इसी तरह से न्याय व्यवस्था और उसके कायदे-कानून तकनीकी दृष्टि से बड़े पेचीदा, खर्चीले और अनावश्यक रूप से समयसाध्य बने हुए हैं, जिनसे न्याय पाने में विलंब होता है और लोग बेवजह सताए जाते हैं। इनमें जरूरी बदलाव अत्यंत आवश्यक है।

इसी तरह व्यवस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता भी सभी महसूस करते हैं। नौकरशाही के जोर के आगे उसमें बदलाव लाना टेढ़ी खीर है, पर उसे करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच की खाई पाटना भी सरल नहीं है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश की आकांक्षाओं को आकार देने का ऐतिहासिक कार्य प्रभावी नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। आशा है नई सरकार इन प्रश्नों पर प्राथमिकता से ध्यान देगी और कार्रवाई करेगी।

अब भी बरकरार है हर पुराना खतरा

राकेश अचल

देश में आम चुनाव हो गए । गठबंधन की नयी सरकार बन गयी । विभागों का वितरण भी हो गया। छत्तीसगढ़ में हिंसा भी हो गयी और सबसे बड़ी बात कि जिस मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री आजतक नहीं बोले उसके बारे में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अधिनायक डॉ मोहन भागवत बोल गए। इस सबके बावजूद असली बात ये है कि चुनाव से पूर्व देश जिन खतरों का सामना कर रहा था, वे सब आज भी बरकरार हैं।

आप गौर से देखें तो ये नई सरकार अल्पमत की और गठबंधन की सरकार जरूर हैं लेकिन इसका केवल नाम बदला हैं, काम नही। नई सरकार के हाथों में आज भी वे सब हथियार और सिपाहसालार हैं जो चुनाव से पहले आपके मंगलसूत्र के लिए खतरा बता रहे थे । आपकी भैंस खोले जाने का हौवा खड़ा कर रहे थे । हिन्दू मुसलमान और धर्म के आधार पर आरक्षण को रोकने की बात कर रहे थे। यानि हौवा भी मौजूद हैं और हौवा खड़े करने वाले भी।

गठबंधन की सरकार में ईडी और सीबीआई जैसे हिंसक चौपाये अभी भी गठबंधन की अगुवाई कर रही भाजपा के पास हैं। यानि विपक्ष को कुचलने और परेशान करने के सारे औजार भाजपा ने अपने हाथों में रखे है। सहयोगी दलों को उन्हें छूने भी नहीं दिया क्योंकि मुमकिन हैं कि आने वाले कल में इन हथियारों का इस्तेमाल भाजपा को अपने गठबंधन के साथियों के खिलाफ ही करना पड़े ! अतीत में भाजपा ने ऐसा किया भी हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिकमत अमली से नए मंत्रियों को विभागों का वितरण किया हैं उससे साफ़ जाहिर हैं कि उनकी निगाहें कहीं और निशाना कहीं और हैं। माननीय का देश को कांग्रेस विहीन करने का सपना अभी मरा नहीं हैं बल्कि शीतनिद्रा में चला गया हैं। जैसे ही आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, जम्मू.कश्मीर और हरियाणा जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा होगी। इस सरकार के छिपे हुए नाखून फिर से बाहर निकल आएंगे । आपको पता है न कि नाखून छिपाने की कला केवल हिंसक प्रवृत्ति के जानवरों में होती है, भले ही वे जंगली जानवर हों या पालतू।

आपको भूलना नहीं चाहिए कि भाजपा 365 दिन, 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी हैं। इसलिए ये पार्टी अपना 2029 और 2047 तक का सपना पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में क्या कुछ करेगी, कहना कठिन हैं। मै तो परामर्श दूंगा कि नयी सरकार में इतने सारे विभागों के साथ एक पृथक विभाग चुनावों का होना चाहिये । इसका प्रभार माननीय प्रधानमंत्री खुद अपने पास रखें। इस विभाग के लिए बजट के साथ ही प्रधानमंत्री केयर फंड की तरह चुनाव केयर फंड भी बनाया जाना चाहिए। इस तरह के फंड का कोई हिसाब-किताब न रखना पड़ता हैं और न देना पड़ता हैं। और यदि गिरीश मुर्मू जैसा सीएजी हो तो इसकी जांच भी कोई नहीं कर सकता।

बहरहाल बात चल रही थी उन खतरों की जो बरकरार है। पहला खतरा संविधान पर ही हैं। माननीय ने भले ही संसदीय दल, गठबंधन और सदन का नेता चुने जाने से पहले संविधान की प्रति को माथे से लगाया था लेकिन देश में शायद ही किसी को इस बात पर यकीन हो कि नयी सरकार संविधान की कसम खाकर सबके साथ सबका विकास करेगी। नई सरकार में देश की 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी का कोई प्रतिनिधि नहीं है। माननीय राष्ट्रपति चाहें भी तो इस समाज के किसी प्रतिनिधि को सदन में नामजद कर उसे मंत्री बनाने के लिए भी नहीं कह सकतीं। उनके हाथ बंधे हैं। यानी भाजपा हिन्दू राष्ट्र तो नहीं बना सकी लेकिन उसने देश को एक हिन्दू सरकार जरूर दे दी, जिसमें भाजपा की दुश्मन नंबर दो मुसलमान बिरादरी नहीं है। भाजपा की दुश्मन नंबर एक तो कांग्रेस है, जो बीते दस साल में मर कर भी नहीं मर रही । हर चुनाव के बाद दोगुने उत्साह से खड़ी हो जाती है। भले ही सत्ता उसके लिए अभी भी कोसों दूर है।

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात संघ प्रमुख डॉ मोहन भागवत का बयान हैं जो उन्होंने नई सरकार को समझाइश बतौर दिया हैं। डॉ मोहन भागवत की भागवत को भाजपा पहले ही सुनने से इंकार कर चुकी है। चुनावों के बीच में ही भाजपा अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने अपने श्रीमुख से कहा था कि भाजपा को संघ की जरूरत नहीं हैं। उन्होंने एकदम सही कहा था । भाजपा को भले संघ की जरूरत न हो किन्तु संघ को तो भाजपा कि जरूरत है। संघ ने तो आज तक नहीं कहा कि उसे भाजपा की जरूरत नहीं हैं । संघ प्रमुख शंकराचार्य की मुद्रा में नयी सरकार को सीख दे रहे हैं कि नई सरकार जलते मणिपुर को देखे। विपक्ष को प्रतिपक्ष समझे। डॉ भागवत ने भाजपा को बेनकाब करते हुए मुजाहिरा किया हैं कि इस बार भी हमने अपने लोकमत जागरण का काम किया है। वास्तविक सेवक मर्यादा का पालन करते हुए चलता है, अपने कर्तव्य को कुशलता पूर्वक करना आवश्यक है, लेकिन क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के असली शंकराचार्यों की बात न मानने वाले लोग संघ के शंकराचार्य की बात मानेंगे ?

चूंकि मै अविनाशी नहीं हूँ इसलिए मेरे पास कोई तीसरा नेत्र नहीं हैं, किन्तु मेरे पास एक अंतर्चेतना हैं जो मुझे आगाह करती है। मुझे लगता हैं कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी, उनकी भाजपा ने अपना एजेंडा नहीं बदला है उसी तरह संघ ने भी अपना एजेंडा नहीं बदला हैं। डॉ भागवत ने कहा- हजारों वर्षों से जो पाप हमने किया, उसका प्रायश्चित करना होगा। भारतोद्भव जो लोग हैं, उनसे मिलना आसान है क्योंकि इसकी एक ही बुनियाद है। वही यम नियमात्मक आचरण का पुरस्कार सर्वत्र है। पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है, सोचना पड़ेगा ? ईसा मसीह की ईसाइयत क्या है, सोचना पड़ेगा । भगवान ने सबको बनाया है।

भगवान की बनाई जो कायनात है, उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए सोचना पड़ेगा। जाहिर हैं कि ये एक छिपी हुई धमकी हैं उन लोगों के लिए जिन्हें भाजपा और संघ भारतीय नहीं मानता। इन लोगों में 20 करोड़ मुस्लिम ही नहीं बल्कि वे लोग भी हैं जो प्रश्न करते हैं, जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होते हैं। जो संविधान की बात करते हैं। जिनकी भाषा माननीयों को अर्बन नक्सलियों की भाषा लगती हैं। जिसे बोलने वाले शाहजादे नजर आते हैं।

बहरहाल गठबंधन नई सरकार को लख-लख बधाइयां, नए मंत्रियों को उनके नए विभाग मुबारक। खासतौर पर मध्यप्रदेश के कोटे से मंत्री बनाये गए मामा शिवराज सिंह को बधाई क्योंकि उन्हें वो जिम्मेदारी दी गयी हैं जो उनके मित्र नरेंद्र सिंह तोमर नहीं निभा पाए थे । तोमर के हिस्से में एक नाकाम कृषि मंत्री होना ही आया था। तोमर के दामन पर 700 किसानों की शहादत के चिन्ह हैं।

शान्ति और सद्भाव सबसे बड़ी जरूरत

पुराने मंत्रियों को नयी सरकार में वही विभाग देकर नरेन्द्र मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश शायद की है कि उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। जिस तरह पिछली दो सरकारें उन्होंने चलाई, इस बार भी वैसे ही चलाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है, जिसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। गृह, रक्षा, विदेश, वित्त और रेल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग अब भी उन्हीं मंत्रियों के पास हैं, जिनके पास पिछली बार थे। जबकि इस बार सरकार का गठन जिस तरह जदयू और तेदेपा के साथ मिलकर हुआ है, उसमें कयास लगाए जा रहे थे कि ये दल अपने लिए महत्वपूर्ण विभाग मांग सकते हैं। अब संभवत: लोकसभा अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा फैसला देखने को मिले। लेकिन पुराने मंत्रियों को नयी सरकार में वही विभाग देकर नरेन्द्र मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश शायद की है कि उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। जिस तरह पिछली दो सरकारें उन्होंने चलाई, इस बार भी वैसे ही चलाएंगे। अपने इस मंसूबे में वे कितने कामयाब होते हैं और क्या उनके गठबंधन के बाकी साथी उनकी कार्यशैली को सहजता से स्वीकार करते हैं, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन देश के जो मौजूदा हालात हैं, उन्हें देखकर प्रधानमंत्री को यह सलाह दी जा सकती है कि वे कम से कम अब घटनाओं और स्थितियों की उपेक्षा करने या अपनी राजनैतिक सुविधा-असुविधा से ऊपर उठकर आम जनता के हित को देखते हुए आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें।

जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, उसी दौरान जम्मू-कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ। वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं को इस बार निशाने पर लिया गया। ऐसी किसी भी घटना की फौरन निंदा होनी चाहिए और मृतकों, घायलों की जाति, धर्म को न देखकर सभी के लिए संवेदना जताई जानी चाहिए। मगर कुछ लोगों ने इसमें भी राजनीति करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर इस घटना के बहाने घृणा फैलाने के प्रयास दिखने लगे। इधर मणिपुर में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने सोमवार को जिरीबाम जा रहे पुलिस काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इसमें एक पुलिस कर्मी घायल हो गया। यह घटना मणिपुर के मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह के जिले के दौरे से ठीक पहले हुई है। अमूमन शांत रहने वाले जिरीबाम जिले में पिछले हफ्ते से तनाव बढ़ रहा है। इसलिए बीरेन सिंह वहां का दौरा करने वाले थे, तभी यह हमला हुआ। इसके बाद से मणिपुर में फिर से जातीय तनाव तेज होने की आशंका जतलाई जा रही है।

वैसे भी एक साल से अधिक वक्त से मणिपुर अशांत है। कुकी और मैतेई समूहों के बीच हुए हिंसक संघर्ष में मानवता ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री से सहज अपेक्षा थी कि वे कम से कम एक बार इस अशांत प्रदेश में जाते और अमन कायम करने की कोशिश करते। लेकिन श्री मोदी ने इस ओर निराश ही किया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी स्थितियों को संभालने में नाकाम रहे हैं, फिर भी पद पर बने ही हुए हैं। एक बार आधे-अधूरे तरीके से इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की, लेकिन इससे राज्य में शांति बहाली नहीं हुई।

अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस मामले में बड़ा बयान देते हुए एक तरह से नयी सरकार को नसीहत दी है। नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर में शांति का इंतजार करते हुए एक साल हो गया है। पिछले 10 सालों से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक राज्य में फिर से बंदूक संस्कृति बढ़ गई। ऐसा लगता था कि पुरानी बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है। वहां अचानक कलह उपज गई या उपजायी गई, उसकी आग में मणिपुर अभी तक जल रहा है, त्राहि-त्राहि कर रहा है और उस पर ध्यान नहीं है? प्राथमिकता देकर इस पर विचार करना हमारा कर्तव्य है। यहां हमारा से आशय निश्चित ही केंद्र सरकार से है। हमारा कहकर संघ प्रमुख ने बता दिया कि भाजपा अब भी उन्हीं की है, अब भाजपा संघ को कितना अपना मानती है और कितना नहीं, यह जे पी नड्डा ही बता सकते हैं।

बहरहाल, संघ प्रमुख की नसीहत बिल्कुल सही है। बंदूक संस्कृति या जातीय, सांप्रदायिक हिंसा के लिए कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आग लगे तो उसे फौरन शांत करने के उपाय होने चाहिए। ऐसा नहीं होने पर कितने गंभीर परिणाम होते हैं, मणिपुर इसका ज्वलंत उदाहरण है। अशांति की चिंगारी इस वक्त छत्तीसगढ़ में भी भड़की है। यहां के बलौदाबाजार में एक उग्र प्रदर्शन में कलेक्टर और एसपी के दफ्तरों में ही आग लगा दी गई, इसके अलावा सौ से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता को भी आतंकित किया गया। हालात ऐसे बन गए कि अब यहां धारा 144 लागू करनी पड़ रही है।

दरअसल 15-16 मई की आधी रात को अज्ञात लोगों ने सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब पांच किमी मानाकोनी बस्ती स्थित बाघिन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैतखाम को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस प्रशासन ने इस पर तत्काल कार्रवाई भी शुरु कर दी, लेकिन सतनामी समाज के लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए। 9 जून को गृहमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश भी दिए और 10 जून को सतनामी समाज के लोगों ने दशहरा मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। लेकिन इस दिन अप्रत्याशित रूप से कम से कम 5 हजार लोगों की भीड़ जमा हो गई और उसके बाद अविचारित हिंसा और तोड़-फोड़ का ऐसा आलम हुआ कि इस राज्य के लोग हतप्रभ हैं। छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से तो ग्रस्त रहा है, लेकिन सांप्रदायिक, जातीय उन्माद के लिए यहां कोई जगह नहीं रही। पिछली भूपेश सरकार के वक्त साजा के बीरनपुर गांव में भुवनेश्वर साहू की हत्या और दो दिन बाद दो मुस्लिम युवकों की हत्या की सांप्रदायिक घटना हुई थी।

इसके बाद अभी दो दिन पहले इसी राज्य के आरंग में मवेशी ले जाने वाले दो लोगों की भीड़ ने हत्या कर दी, जिसकी जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। और अब बलौदाबाजार की घटना हो गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की है। राज्य सरकार तो अपने स्तर और क्षमता के अनुरूप काम कर ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है, जिन राज्यों में अब तक शांति बनी रहती थी, वहां इस तरह की घटनाएं क्यों होने लगी हैं। अमन और सद्भाव इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है।

संपादकीय

पर्यावरण बने प्राथमिकता

धरती का तापमान बढ़ना आज विश्व के समक्ष सबसे बड़ा संकट है, जिसका तात्कालिक समाधान नहीं किया गया, तो मानव समेत तमाम जीवों का अस्तित्व निश्चित ही खतरे में पड़ जायेगा. इस संकट के प्रभाव के गंभीर परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, बेमौसम व औचक बरसात, चक्रवात, आंधी, वनों में आग, भू-स्खलन, ग्लेशियरों में बर्फ पिघलना, समुद्र का तापमान बढ़ना और समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी आदि जैसी समस्याएं सघन हो रही हैं.

विश्व पर्यावरण दिवस, जो हर साल पांच जून को मनाया जाता है, के अवसर पर इस वर्ष का मुख्य विषय 'भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा निरोध' है. पर्यावरण का समुचित संरक्षण नहीं होने तथा भूमि की उर्वरा को बनाये रखने के प्रति समुचित संवेदनशीलता की कमी से भारत समेत कई देश भूमि क्षरण की समस्या का सामना कर रहे हैं. बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई, भूजल के अत्यधिक दोहन तथा रासायनिक खेती के कारण भूमि क्षरित हो रही है.

इससे मरुस्थलीकरण भी बढ़ रहा है. अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रेखांकित किया है कि मानवता भूमि पर निर्भर है, फिर भी समूचे विश्व में प्रदूषण, जलवायु अव्यवस्था और जैव-विविधता के ह्रास से स्वस्थ भूमि मरुभूमि में तथा जीवंत पारिस्थितिकी मृत क्षेत्र में परिवर्तित हो रही हैं. पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न प्रयासों के साथ-साथ इस ओर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है. दुनियाभर में तीन अरब से अधिक लोग भूमि क्षरण से प्रभावित हैं.

साथ ही, पीने योग्य पानी का तंत्र भी तबाह हो रहा है. भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश को स्वस्थ भूमि और जैव-विविधता की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक है. इस संबंध में भारत सरकार की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं, पर इस प्रक्रिया में हम सभी की भागीदारी आवश्यक है. कम पानी एवं खाद की आवश्यकता वाले तथा अधिक पौष्टिक मोटे अनाजों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी पहल है. स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक देश आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में यह संकल्प रखा था कि हमारा देश 2070 तक कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य के स्तर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है. स्वच्छ ऊर्जा के अधिक उत्पादन से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भी घटेगी, जिनके खनन, वितरण, ऊर्जा उत्पादन और उपभोग से पारिस्थितिकी को भारी नुकसान होता है. जिस प्रकार हम प्रकृति से स्वच्छ ऊर्जा हासिल कर रहे हैं, उसी तरह हमें वर्षा जल के संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए. पर्यावरण बचाने के लिए व्यक्तिगत और स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक साझा प्रयासों की आवश्यकता है.

पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण जरूरी

हर साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस पांच जून को मनाया जाता है। इस मौके पर अलग-अलग तरीके से पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। आज पूरे विश्व में प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति और जनजीवन दोनों खतरे में हैं।

जीवन जीने के लिए प्रकृति का सुरक्षित होना काफी ज्यादा जरूरी है और यह जिम्मेदारी हम सभी की बनती है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखें और हरियाली बनाए रखें।

हम छोटे-छोटे कदम उठाकर, जैसे कम पानी और बिजली का इस्तेमाल करना, कचरे को कम करना और उसका पुनर्चक्रण, पौधे लगाना, वाहनों का कम इस्तेमाल करना आदि पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में योगदान दे सकते हैं। पृथ्वी को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करना हमारा सामूहिक दायित्व है।

क्या आप वाकई में है कामयाब..!

जरूरी नहीं कि हर कामयाब दिखने वाला व्यक्ति सचमुच कामयाब हो। आमतौर पर जो ताकतवर है, पैसेवाला है, वैभवपूर्ण जीवन जीते दिखाई पड़ता है, उसे कामयाब मान लिया जाता है। फिर यदि ये कहा जाए कि जिसके पास ये सबकुछ है वो खुश नहीं है, परेशान रहता है, बीमारियों और बुरी लतों से घिरा हुआ है तो? तब भी कई लोग आंखों पर पट्टी बांधे यही सोचेंगे नहीं हमें ये सब मिलेगा तो हम बहुत खुश रहेंगे। दरअसल, वैभव, धन, ताकत में कोई बुराई नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने इनका सही इस्तेमाल किया है, उन्हें ही दुनिया याद रखती है। फिर ऐसे भी बहुत से लोग हैं, जिनके पास ये सबकुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया को वो सबकुछ दिया, जो कोई ताकतवर इंसान दे सकता था। यूं तो उदाहरणों कोई कमी नहीं, लेकिन सैंकड़ों साल बाद भी जिन दो हस्तियों का हम समाज में महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं, उन्हें उदाहरण के तौर पर अपने सामने रखते हैं।

हम अपने आसपास जो भी लोग दूसरों पर अधिकार जमाते दिखते हैं, ज्यादा धनवान दिखते हैं, ज्यादा लोगों के बीच पूछ परख वाले दिखते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। बहुत से तो ऐसे भी हैं, जो ऐसे लोगों के इर्दगिर्द बने रहने या उनके खास लोगों की सूची में शामिल होने को ही कामयाबी समझते हैं। आरामदायक जिंदगी को भी कामयाबी कहा जाता है, तो औरों की तारीफों में कई लोग अपनी कामयाबी को तलाशते हैं।

फार्मा सेक्टर से बढ़ते निर्यात का परिदृश्य

डा. जयंतीलाल भंडारी

निश्चित रूप से भारत के फॉर्मा सेक्टर का बढ़ता निर्यात भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष है। देश से दवाओं का निर्यात 2023-24 में सालाना आधार पर 9.67 फीसदी बढक़र 27.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। जबकि देश के विभिन्न उत्पादों के कुल निर्यात में तीन प्रतिशत की गिरावट रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में अकेले अमेरिका को भारत से 7.83 अरब डॉलर की दवा का निर्यात किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान निर्यात का यह आंकड़ा 25.4 अरब डॉलर रहा था। यह कोई छोटी बात नहीं है कि कोरोनाकाल में फॉर्मा और मेडिकल सेक्टर की कई वस्तुओं का भारत बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। भारत दुनिया में पीपीई किट, सर्जिकल मास्क और मेडिकल गॉगल्स का बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहा है। अब उन देशों में भी भारत की सस्ती दवाइयों की मांग बढ़ रही है जिन्हें भारत की सस्ती दवा पर बहुत भरोसा नहीं था। भारत से फार्मास्युटिकल निर्यात दुनिया भर के कोई 200 देशों तक पहुंचता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अत्यधिक विनियमित बाजार शामिल हैं। स्थिति यह है कि दवाई उद्योग की वैश्विक श्रृंखला के बाधित होने से इस समय भारत की फॉर्मा कंपनियों को विभिन्न दवाइयों की आपूर्ति के ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि इस समय पूरी दुनिया में भारत अपनी दवाओं की कम लागत और उच्च गुणवत्ता के कारण विश्व की नई फार्मेसी के रूप में रेखांकित हो रहा है। भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग मात्रा के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के मामले में 14वां सबसे बड़ा उद्योग है तथा फार्मा सेक्टर वर्तमान में देश की जीडीपी में लगभग 1.72 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।

इस समय भारत के दवा उद्योग में करीब 3000 दवा कंपनियों और 10500 विनिर्माण इकाइयों का विशाल नेटवर्क शामिल है। भारत को वैश्विक फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। देश में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक बड़ा समूह है जो फॉर्मा उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है। ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग से 100 फीसदी तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है और इससे अधिक सरकारी अनुमोदन के माध्यम से है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफरा-तफरी है और चीन में निवेश करने वाली कई कंपनियां अन्य देशों में विकल्प की तलाश में हैं। ऐसे में चीन में कार्यरत कई कंपनियों सहित दुनिया के कई देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। इन सब कारणों से भारत में फॉर्मा सेक्टर का आकार बढ़ रहा है। यदि हम भारत के फॉर्मा सेक्टर में तेजी से बढऩे के कारणों की ओर देखें तो पाते हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है और अपने किफायती टीकों और जेनेरिक दवाओं के लिए जाना जाता है। जेनेरिक दवाएं, ओवर दि काउंटर दवाएं, थोक दवाएं, टीके, अनुबंध अनुसंधान और विनिर्माण, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स भारतीय फार्मा उद्योग के कुछ प्रमुख खंड हैं। चूंकि भारत में दवाई उत्पादन की लागत अमेरिका एवं पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम है, इसी कारण भारत घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण, उच्च गुणवत्ता और कम लागत वाली दवाओं के निर्माण में एक प्रभावी भूमिका निभा रहा है। दुनिया की करीब 70 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होती है।

जेनेरिक दवाओं की अफ्रीका की कुल मांग का 50 प्रतिशत, अमेरिका की मांग का 40 प्रतिशत तथा ब्रिटेन की कुल दवा मांग का 25 प्रतिशत हिस्सा भारत से ही जाता है। दुनिया की 60 फीसदी वैक्सीन का भी उत्पादन भारत में होता है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनिवार्य टीकाकरण योजनाओं के लिए 70 प्रतिशत टीकों की आपूर्ति भारतीय दवाई निर्माता कंपनियों के द्वारा की जाती है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे अधिक फार्मास्युटिकल विनिर्माण सुविधाएं हैं जो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) के अनुपालन में हैं और यहां 500 एपीआई उत्पादक हैं जो दुनिया भर के एपीआई बाजार का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।

यह बात ध्यान रखी जानी होगी कि मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के बावजूद, भारतीय फार्मा-मेडटेक क्षेत्र सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) और प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम) पर उच्च स्तर की आयात निर्भरता, उच्च स्तरीय स्कैनिंग और इमेजिंग उपकरणों में कम तकनीकी क्षमताओं जैसी चुनौतियों से ग्रस्त है

केंद्र सरकार ने दवाई उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने, अधिक कीमतों वाली दवाइयों के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देने और चीन से होने वाले दवाइयों के कच्चे माल-एपीआई (एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इंग्रीडिएंट्स) के भारत में ही उत्पादन हेतु कोई ढाई वर्ष पहले शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स (पीएलआई) स्कीम के लाभ मिलना शुरू हो गए हैं। 40 से अधिक कंपनियां पीएलआई स्कीम के तहत फार्मा के कच्चे माल का उत्पादन शुरू कर चुकी हैं या जल्द ही करने वाली हैं। ये कंपनियां अफ्रीका के कुछ देशों में फार्मा के कच्चे माल का निर्यात भी कर रही हैं। यदि हम फार्मा के साथ मेडिकल डिवाइस के निर्यात को देखें तो पाते हैं कि इसमें भी पिछले दो-तीन सालों से 12-15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी मेडिकल डिवाइस का आयात अधिक हो रहा है और पिछले साल यह आयात 60000 करोड़ रुपए का रहा।

मेडिकल क्षेत्र से जुड़े डिस्पोजेबल आइटम, आर्थोपेडिक आइटम, सीरिंज, निडल, ग्लाव्सद जैसे कई आइटम में दुनिया के बाजार में भारत का बोलबाला है। सरकार ने मेडिकल डिवाइस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीति की घोषणा की है और इस पर अमल के बाद मेडिकल डिवाइस का आयात कम होने के साथ निर्यात भी बढ़ेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत में सस्ती दवाइयों और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के लिए कई विकसित देशों के मरीज भी भारत का रुख कर रहे हैं। भारत में चिकित्सा सेवा की लागत पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम है और भारत दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे सस्ता है। भारत को चिकित्सा पर्यटन के लिए दुनिया में लाभप्रद जगह माना जा रहा है। वैश्विक मेडिकल टूरिज्म के लिए दुनिया के पहले दस देशों में भारत का नाम रेखांकित हो रहा है। निश्चित रूप से देश के फॉर्मा सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए शोध एवं अनुसंधान विकास के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा। फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में नवाचार के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारत में फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर एक राष्ट्रीय नीति शुरू की गई है।

योजना का उद्देश्य भारतीय फार्मा-मेडटेक क्षेत्र को लागत आधारित से नवाचार आधारित विकास बदलना है। यह नीति नई दवाओं, टीकों, निदान और उपकरणों की खोज और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करती है। यह बात ध्यान रखी जानी होगी कि मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के बावजूद, भारतीय फार्मा-मेडटेक क्षेत्र सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) और प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम) पर उच्च स्तर की आयात निर्भरता, उच्च स्तरीय स्कैनिंग और इमेजिंग उपकरणों में कम तकनीकी क्षमताओं जैसी चुनौतियों से ग्रस्त है।

बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर और अन्य उभरते उत्पादों के विकास की गति धीमी है। फार्मा और मेडटेक में हमारा अनुसंधान एवं विकास निवेश अन्य देशों से पीछे है। इस परिदृश्य को बदलना होगा। निश्चित रूप से फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में मजबूत अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता।

बढ़ती पर्यावरणीय चेतना

कुलभूषण उपमन्यु,

चिमटघाटी गांव (झारखंड) के लोगों ने सरकारी स्वीकृति के बाद भी सडक़ इसलिए नहीं बनने दी कि इससे पेड़ काटे जाने थे। उन्होंने कहा कि ये पेड़ हमारे पूर्वजों की विरासत हैं, जिसे ऐसे ही आगे की पीढ़ी को सौंपना है। उज्जैन (मध्य प्रदेश) के कोठी रोड पर पुराने पेड़ों को काटने का विरोध लोगों ने किया एवं 2 मई को तख्तियां लेकर प्रदर्शन भी किया। कलेक्टर एवं पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर से चर्चा कर पेड़ों को बचाने हेतु गुहार लगाई। हरिओम वृक्ष मित्र सेवा समिति तथा एक फेसबुक समूह 'रूपांतरण' ने भी काफी सक्रियता दर्शाई। खेरवाडी गांव (शिवाजी नगर क्षेत्र, पुणे) के 10 हजार लोगों ने पानी की समस्या से त्रस्त होकर चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया एवं जगह-जगह 'पानी नहीं तो वोट नहीं' के पोस्टर लगाए। ये सारे प्रसंग पर्यावरणीय चेतना को दर्शाते हैं। ऐसी ही चेतना यदि विकसित होती रही तो आगामी चुनाव में पर्यावरण का मुद्दा बनना लगभग निश्चित लगता है। इन प्रयासों के बावजूद हमें यह ध्यान रखना है कि अभी भी पर्यावरण के लिए काफी कुछ किया जाना शेष है।

हालांकि पर्यावरण के नाम पर हमारे राजनीतिज्ञ आम तौर पर मुंह बिचकाते हैं और अक्सर इसे विकास के बरअक्स खड़ा कर देते हैं, लेकिन सत्तर-अस्सी के दशक के बाद आम लोगों ने इस मसले को तरजीह देना शुरू कर दिया है। हाल के आम चुनाव में भी कई स्थानों पर पर्यावरण के मुद्दों को उछाला गया है। इस आलेख में पर्यावरण के मसले को खंगालने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस, 05 जून के एक दिन पूर्व देश की लोकसभा के चुनाव परिणाम घोषित होने से प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में इसकी बहुलता रहेगी एवं पर्यावरण किनारे पर। इस लोकसभा चुनाव में बिगड़ा पर्यावरण राजनीतिक दलों का प्रमुख मुद्दा नहीं बना, परन्तु दोनों प्रमुख दलों ने अपने-अपने घोषणापत्रों में इसे अंतिम पृष्ठों पर स्थान जरूर दिया। लोकसभा चुनाव में बिगड़ा पर्यावरण भले ही प्रमुख चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया हो, परन्तु पिछले 5-6 महीनों की घटनाओं पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि अब पर्यावरणीय चेतना बढ़ रही है। कई सामाजिक संगठनों एवं जन आंदोलनों ने स्वतंत्र या संयुक्त रूप से जारी अपने प्रयत्नों में पर्यावरण के मुद्दों का जिक्र किया एवं चुनाव प्रचार के समय प्रत्याशियों से इस पर चर्चा भी की। दिल्ली के लगभग 2500 से ज्यादा रहवासी कल्याण संगठनों (रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) ने संयुक्त रूप से 'यूनाईटेड रेजीडेंट ज्वाइंट एक्शन ऑफ दिल्ली' के बैनर तले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 24 बिंदुओं वाला एक नागरिक घोषणापत्र जारी किया जिसमें प्रमुख मुद्दा दिल्ली को प्रदूषण एवं ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने का था।

दिल्ली के अलावा मुम्बई में भी कई संगठनों (नेट कनेक्ट), वायर फाउंडेशन, सागर शक्ति, वेटलेंड्स एंड हिल्स तथा एलायंस फार रिवर्स के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अपने अभियान में सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर मांग की कि वे पर्यावरण एवं प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के प्रयासों का उल्लेख अपने घोषणापत्रों में जरूर करें। इसी प्रकार 86 नागरिकों तथा जनआंदोलन से जुड़े संगठनों ने एक राष्ट्रीय मंच के तहत आम चुनाव 2024 के संदर्भ में एक जन घोषणापत्र जारी किया। इसमें देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों के साथ परिस्थितिकी सुरक्षा (इकोलाजिकल कंजर्वेशन) सुनिश्चित करने की मांग भी की गई। इसके तहत विलुप्त होती प्रजातियों को बचाना, वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण तथा भोज्य पदार्थों में कीटनाशी की विषाक्तता रोकने तथा प्लास्टिक पर रोक लगाने की बातें प्रमुख हैं। ऊर्जा की बचत एवं पर्यावरण सुरक्षा के नियम-कानूनों को सख्त करने के साथ-साथ चुनाव तथा मानव अधिकार आयोग के समान एक स्वतंत्र, संवैधानिक इकाई, राष्ट्रीय पर्यावरण आयुक्त बनाने का सुझाव भी दिया गया। देश के पर्यावरण से जुड़े 70 समूहों ने हिमालय क्षेत्र को सुरक्षित रखने हेतु वहां बांध, रेलवे, जलविद्युत, चार लेन राजमार्ग एवं वन कटाई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि योजनाओं के लिए जनमत संग्रह एवं सार्वजनिक विचार-विमर्श अनिवार्य बनाया जाए। इसी वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में लद्दाख के करीब 30 हजार लोगों ने कडक़ती ठंड में अपने वन, पानी, भूमि एवं रोजगार आदि के लिए प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में प्रदर्शन एवं आंदोलन किया। पर्यावरण संरक्षण को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग भी की गई।

इसे देखकर पश्चिम बंगाल के कुछ नेताओं ने दार्जिलिंग के लिए इसी प्रकार की मांग रखी। पर्यावरण सुरक्षा हेतु विभिन्न संगठनों की मांग के साथ-साथ पर्यावरण चेतना के कई प्रसंग भी सामने आए। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आत्माराम सनातन धर्म कालेज में आयोजित युवा संसद में छात्र-छात्राओं ने दिल्ली के दमघोंटू प्रदूषण को चुनावी मुद्दा बनाने की बात बेबाकी से रखी। मुम्बई में कई क्षेत्रों में मतदाताओं ने दलों के प्रत्याशियों के सामने प्रदूषण कम करने एवं हरियाली बचाने के प्रयास करने हेतु कहा। कुछ प्रत्याशियों ने अपने वादों में साफ हवा रखने का जिक्र भी किया। राजेंद्र नगर (हैदराबाद के पास) स्थित तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने सरकार के उस आदेश का विरोध किया जिसमें हाईकोर्ट भवन बनाने हेतु लाखों पेड़ काटे जाना प्रस्तावित था। इसे लेकर जनवरी माह में कई दिनों तक प्रदर्शन किए गए एवं पेड़ों से लिपटकर उन्हें बचाने का संकल्प लिया गया। चिमटघाटी गांव (झारखंड) के लोगों ने सरकारी स्वीकृति के बाद भी सडक़ इसलिए नहीं बनने दी कि इससे पेड़ काटे जाने थे। उन्होंने कहा कि ये पेड़ हमारे पूर्वजों की विरासत हैं, जिसे ऐसे ही आगे की पीढ़ी को सौंपना है। उज्जैन (मध्य प्रदेश) के कोठी रोड पर पुराने पेड़ों को काटने का विरोध लोगों ने किया एवं 2 मई को तख्तियां लेकर प्रदर्शन भी किया। कलेक्टर एवं पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर से चर्चा कर पेड़ों को बचाने हेतु गुहार लगाई। हरिओम वृक्ष मित्र सेवा समिति तथा एक फेसबुक समूह 'रूपांतरण' ने भी काफी सक्रियता दर्शाई।

बढ़ते एनपीए की समस्या का समाधान जरूरी

सत्यपाल वशिष्ठ

भारत की बैंकिंग प्रणाली लंबे समय से एनपीए की समस्या से ग्रस्त है। इससे बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के साथ-साथ लाभ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार सार्वजनिक बैंकों में अपनी पूंजी लगाकर क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है। एनपीए की राशि इस समय 7 लाख करोड़ है जो चिंता का विषय है, क्योंकि यह राशि किसी भी काम की नहीं है। बैंकों का एनपीए दो स्थितियों में बढ़ता है। एक जब अर्थव्यवस्था में कारोबार सुस्त रहता है। दूसरा जब कोई व्यक्ति या कंपनी जानबूझ कर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाता है। इन्हें विल्फुल डिफाल्टर कहते हैं। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री ने लोकसभा में बताया कि 31 मार्च 2023 को भारत में 2623 इरादतन चूककर्ता हैं। इन उधारकर्ताओं ने 196049 करोड़ रुपए भारतीय बैंकों के देने हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ने भारतीय बैंकों को 22000 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया और देश छोडक़र भाग गए। आरबीआई के अनुसार बैंकों ने 2012-13 से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के ऋण राइट ऑफ किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक एवं निजी बैंकों ने 172800 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए, जो कि तीन महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों मनरेगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में से किसी एक को 2023-24 के बजट में आबंटित राशि से कहीं ज्यादा था। इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट जगत की फर्मों को प्रदान किया गया है। खुदरा उधार कर्ताओं द्वारा किए डिफॉल्ट बहुत ही कम हैं।

एनपीए की सकल राशि भारत सरकार के एक साल के आम बजट की एक-तिहाई के बराबर है। एनडीए सरकार ने सार्वजनिक बैंकों को पुनर्पूंजीकरण के लिए 2.76 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक को जब किसी परिसंपत्ति (असेट्स) से आय अर्जित होना बंद हो जाती है, तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। अगर व्यक्ति लगातार 3 महीने तक मासिक किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता तो बैंक को अपने बही-खाते में यह राशि एनपीए के रूप में दर्ज करनी होगी। इस तरह 90 दिन तक मूलधन या ब्याज की किस्त का भुगतान न होने पर लोन खाता एनपीए बन जाता है। एनपीए का मतलब यह नहीं कि बैंक की रकम डूब गई है या बैंक ने इसे वसूलना छोड़ दिया है। लोन को राइट ऑफ करने के बाद भी बैंकों को विभिन्न तरीकों द्वारा रिकवरी करनी पड़ती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार बैंकों ने 109186 करोड़ रुपए (18.6 प्रतिशत) कुल राइट ऑफ राशि, जो 586891 करोड़ रुपए थी, से पिछले 3 वर्षों मे रिकवर किया है। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था फल-फूल रही थी, जिसके कारण बैंकों ने व्यापारियों और कंपनियों को काफी मात्रा में ऋण प्रदान किए। हालांकि यह कंपनियां अपना काम अच्छा नहीं कर पा रही थीं और अपना कर्ज भी नहीं चुका पा रही थी। एनपीए यूपीए सरकार की नीतियों से बढ़ा क्योंकि उस समय ज्यादा से ज्यादा ऋण दिए गए। एवरग्रीनिंग ऋण देना, यह एक ऐसी प्रेक्टिस थी जिसमें उधार लेने वालों को और अधिक उधार दिया जाता है, चाहे उसने ऋण की अदायगी बंद भी कर दी है, ताकि ऋण बही-खाते में दिया हुआ दर्शाया जा सके।

गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बैंकों के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। यही बैंकों के पतन का कारण है। जब एनपीए बढ़ता है तो बैंकों को ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। इससे उनकी फंड जुटाने की लागत बढ़ती है जिसका बोझ ग्राहकों पर ऊंची ब्याज दरों के रूप में पड़ता है। जब कर्ज फंस जाता है तो उसकी प्रोविजनिंग के लिए मुनाफे से एक निश्चित राशि अलग रखनी होती है। मुनाफा कम होने पर बैंकों के विस्तार और ग्राहक सेवाओं पर असर होता है। एनपीए बैंक की वित्तीय अवस्था को मापने का पैमाना है। यह अर्थव्यवस्था पर बोझ होता है। बैड लोन से बैंकों के लाभांश में कमी आती है जिससे बैंकों के लिए ऋण देना मुश्किल हो जाता है और निवेश में कमी आने लगती है।

मुख्यमंत्री ने सपरिवार अपने निवास परिसर में रोपा नीम, रुद्राक्ष और चीकू का पौधा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय एवं परिवार जनों के साथ अपने निवास परिसर में चीकू, नीम और रुद्राक्ष का पौधा रोपा। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपने घरों में और आस-पास पौधा लगाने और पौधों को जीवित रखने की जिम्मेदारी लेने की अपील की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आने वाले मानसून में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और अपने घर, आसपास के परिवेश, गांव और शहरों और जंगलों को खूब हरा-भरा बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर डीएफओ श्री लोकनाथ पटेल, एसडीओ श्री व्ही. एन. मुखर्जी एवं मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे।

सुशासन के लिए होगा आईटी का इस्तेमाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव की सरकार सुशासन लाने के लिए आईटी का बड़े पैमाने में इस्तेमाल करेगी। जनकल्याणकारी योजनाओं से मॉनिटरिंग से लेकर वित्तीय प्रबंधन करों की वसूली, भूमि संबंधी रिकार्ड के पंजीयन, संधारण और संशोधन सहित सभी जरूरी क्षेत्रों में आईटी का इस्तेमाल होगा। सरकार द्वारा लोगों तक शासकीय योजनाओं की पहुंच का दायरा बढ़ाने के साथ ही प्रशासन को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस पहल करने जा रही है। सरकार के बजट में इन सभी विषयों को शामिल किया गया है। जनकल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अटल डैशबोर्ड की शुरूआत की गई है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर हाल में ही देश के जाने-माने विशेषज्ञों के साथ आईआईएम रायपुर में दो दिनों तक बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सुशासन तथा नागरिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी उपायों का चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में रायपुर-भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों के स्टेट कैपिटल के रूप में विकसित कर विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर तैयार करने का लक्ष्य है। सभी विभागों में आई.टी. के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नवा रायपुर, अटल नगर में लाईवलीहुड सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने का लक्ष्य है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इन्यूबेशन सेंटर की स्थापना तथा बी.पी.ओ. एवं के.पी.ओ. को आकर्षित करने के लिए आई.टी. पार्क की स्थापना की भी योजना है। नवा रायपुर में आई.टी. आधारित रोजगार सृजन हेतु प्लग एण्ड प्ले मॉडल का विकास किया जायेगा, इससे आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के नये अवसर विकसित होंगे।

बजट में छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स की स्थापना सहित प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई.गवर्नेन्स के तहत बजट एण्ड अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किये जाने हेतु (जीआईएस) आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा। शासकीय धन के आय.व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली 2.0 प्रारंभ की जायेगी। पीएम वाणी के अंतर्गत प्रथम चरण में एक हजार ग्राम पंचायतों में वाई.फाई के माध्यम से हॉट-स्पॉट इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। वस्तु एवं सेवाकर के संकलन में सुधार एवं पारदर्शिता के लिए राज्य मुख्यालय में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर संबंधी अपीलीय मामलों के त्वरित निराकरण हेतु अधिकरण की स्थापना की जाएगी।

राज्य सरकार की सुध से खेती-किसानी को नया सम्बल

रायपुर। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और यह धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अल्पावधि में राज्य के किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं, इससे राज्य में खेती-किसानी को नया सम्बल मिला है। किसान बेहद खुश है। उनके मन में एक नई उम्मीद जगी है।

छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी तथा दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान करके एक ओर जहां अपना संकल्प पूरा किया है, वहीं दूसरी ओर किसानों से बीते खरीफ विपणन वर्ष में 144.92 लाख मेट्रिक टन धान की रिकार्ड खरीदी की है। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 31,914 करोड़ रूपए का भुगतान एवं किसान समृद्धि योजना के माध्यम से मूल्य की अंतर की राशि 13,320 करोड़ का भुगतान करके यह बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का रास्ता खेती-किसानी से ही निकलेगा। किसानों का मानना है कि राज्य सरकार के अब तक के फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार किसानों की हितैषी है। खेती-किसानी ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल कृषि के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प के मुताबिक समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 917 रूपए के मान से अंतर की राशि भी दे दी है। किसानों को प्रति क्विंटल के मान से 3100 रूपए के भुगतान की यह राशि देश में सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस साल के बजट में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनव पहल की जा रही है। जशपुर जिले के कुनकुरी में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र तथा बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, सूरजपुर जिले के सिलफिली एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, तथा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खडगंवा में कृषि महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था बजट में की है।

कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का निर्माण, दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय तथा रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। राज्य के किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8 हजार 500 करोड़ का लक्ष्य तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता हेतु दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सौर सुजला योजना के माध्यम से सिंचित रकबे में बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जा रहा है। नवीन सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रूपए, लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं के लिए 692 करोड़ रूपए, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ रूपए एवं एनीकट तथा स्टाप डेम निर्माण के लिए 262 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार, कृषि एवं सहायक गतिविधियां के लिए समन्वित प्रयास पर राज्य सरकार का फोकस है। चालू वित्तीय वर्ष कृषि बजट 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 13 हजार 435 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8500 करोड़ रूपए की साख सीमा छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वर्तमान खरीफ सीजन को देखते हुए राज्यभर की सहकारी समितियों में सोसायटियो में गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज भंडारण एवं उठाव की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को खाद-बीज के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अपने खेती-किसानी के दीर्घ अनुभव के आधार पर कहा है कि खरीफ सीजन में किसान भाईयों द्वारा डी.ए.पी. खाद की मांग ज्यादा की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए डी.ए.पी. खाद की मांग और सप्लाई पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। खाद-बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सेंम्पलिंग एवं प्रयोगशाला के माध्यम से जांच का विशेष अभियान संचालित किया जाए।

खरीफ सीजन 2024-25 के लिए राज्य में 13.68 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों की मांग के विरूद्ध अब तक 9.13 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है, जो मांग का 67 प्रतिशत है। सोसायटियों में विभिन्न खरीफ फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। खरीफ सीजन 2024-25 में 5 लाख 59 हजार 203 क्विंटल बीज की मांग के विरूद्ध 6 लाख 39 हजार 4 क्विंटल बीज उपलब्ध है, जो कि मांग का 114 प्रतिशत है। सोसायटियों से किसान लगातार बीज का उठाव कर रहे है। अब तक 03 लाख 75 हजार क्विंटल बीज का उठाव किसानों ने किया है, जो कि बीज की डिमांड का 67 प्रतिशत है।

घरेलु बिजली दर में 20 पैसे युनिट की वृद्धि

रायपुर। बिजली कंपनी को हो रहे नुकसान के चलते छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलु बिजली की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि करने की घोषणा की है। बीते वर्षों में बिजली कंपनी को 4 हजार 4 सौ करोड़ का घाटा हुआ है। बिजली विभाग को 20 फीसदी का नुकसान हुआ है। जिसको लेकर राज्य सरकार ने बिजली कंपनी को घाटे की भरपाई के लिए 1 हजार करोड़ का अनुदान दिया है। अब बिजली की दरों में 8.35 फीसदी की वृद्धि होगी और 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से रेट में बढ़ोत्तरी होगी।

नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत कुमार वर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस लेकर बिजली की नई दरों का ऐलान किया है। पहले सौ यूनिट तक बिजली की दर तीन रूपए सत्तर पैसे थी, जिसमें 20 पैसे की बढ़ोत्तरी की गई है। कुल मिलाकर सौ यूनिट तक की बिजली 3.90 रूपए हो गई है। इसी तरह सौ यूनिट से अधिक और दो सौ यूनिट तक बिजली की दरें 3.90 रूपए थी जो कि बढकर 4.10 रूपए हो गई है। आयोग ने 201 से 400 यूनिट तक बिजली की दरें 5.30 रूपए बढ़ाकर 5.50 रूपए कर दी है। इसी तरह 401 से 600 यूनिट तक दरें 6.30 रूपए से बढकर 6.50 रूपए हो गई है। 601 या उससे अधिक की दरों में 20 पैसे की बढ़ोत्तरी रखी गई है जो कि 7.90 रूपए से बढ़ाकर 8.10 रूपए कर दी गई है। आयोग ने गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली में भी 20 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए सौ रूपए प्रति एचपी बिजली की दर थी। प्रति यूनिट बिजली 5.05 रूपए यूनिट से बढ़ाकर 5.30 रूपए कर दी गई है। कृषि संबंधी अन्य का मांग आधारित 15 किलोवॉट से 112.5 किलोवॉट तक 200 रूपए प्रति किलोवॉट बिजली की दर 5.65 यूनिट थी जो कि बढ़कर 6.25 रूपए हो गई है।

उन्होंने बताया कि 25 एचपी तक (आटा चक्की/पॉवर लूम) 80 रूपए प्रति माह भुगतान करना होगा। बिजली की दर 4.15 रूपए प्रति यूनिट थी जिसे बढ़ाकर 4.75 रूपए कर दी गई है। सरगुजा और बस्तर प्राधिकरण में आने वाले क्षेत्र के लिए 25 एचपी तक आटा चक्की और पॉवरलूम को बढ़ाकर 80 रूपए प्रति माह किया गया है। बिजली की दर 3.75 रूपए से बढ़ाकर 4.25 प्रति यूनिट किया गया है। 25 एचपी तक औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 1.20 रूपए प्रति किलोवॉट भुगतान करना होगा जिसे बढ़ाकर 4.15 रूपए से 4.75 रूपए कर दिया गया है। 25 एचपी से अधिक डेढ़ सौ एचपी तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को डेढ़ सौ रूपए प्रति किलोवॉट दर भुगतान करना होगा। इस श्रेणी के बिजली की दरें 5.90 रूपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6.50 रूपए कर दिया गया है। आईटी, निर्यात आधारित उद्योग को डेढ़ सौ रूपए बिजली प्रति किलोवॉट प्रतिमाह देना होगा। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली 5.15 रूपए से बढ़ाकर 5.75 रूपए कर दी गई है।

केंद्र सरकार जल्द लागू करेगी न्यू टोल टैक्स सिस्टम

नई दिल्ली। भारत सरकार देश में सैटेलाइट आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन शुरू करने की योजना बना रही है। सबसे पहले इसे कॉमर्शियल वाहनों के लिए लागू किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्राइवेट कार, जीप और वैन के लिए भी इस तकनीक को लागू किया जाएगा। इस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (त्वहस्स) को अगले दो साल में सभी टोल कलेक्शन पॉइंट्स पर स्थापित करने की प्लानिंग चल रही है। इससे नई तकनीक की वजह से टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। इस तकनीक के तहत उपयोगकर्ता को जितनी दूरी का सफर करना होगा, उसके हिसाब से टोल का भुगतान करना होगा। त्वहस्स आधारित टोल सिस्टम बैरियर-फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन होगा, जिसमें वाहन के मूवमेंट को ट्रैक करके यह

निर्धारित किया जाएगा कि उस वाहन ने कितने किलोमीटर की यात्रा की है।

मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के तहत काम करने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने GNSS-बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को भारत में लागू करने के लिए ग्लोबल कंपनियों को इनवाइट किया है। हर टोल प्लाजा में दो या उससे ज्यादा GNSS लेन होंगी, जिनमें अग्रिम रीडर होंगे जो GNSS वाहनों की पहचान करेंगे। GNSS लेन में प्रवेश करने वाले गैर-GNSS वाहनों से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। त्वहस्स बेस्ड टोलिंग सिस्टम को पहले तीन महीनों में 2,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लागू किया जाएगा। इसके बाद अगले नौ महीनों में इसे 10,000 किमी तक और 15 महीनों में 25,000 किमी टोल राजमार्गों और 50,000 किमी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

बता दें कि वर्तमान में भारत में फास्टैग इकोसिस्टम मौजूद है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक का यूज किया जाता है, जिसे 2015 में फास्टैग के रूप में पेश किया गया था।

डोसा, इडली बनाने के मिश्रण को सत्तू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी

नयी दिल्ली। इडली, डोसा और खमन बनाने के मिश्रण को सत्तू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए। गुजरात अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण (जीएएआर) ने यह फैसला सुनाया है। गुजरात स्थित किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड ने जीएसटी अग्रिम प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ एएएआर से संपर्क किया था। कंपनी ने कहा था कि उसके सात इंस्टेंट आटा मिक्स तैयार भोजन नहीं है और उन्हें खाना पकाने की कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।

कंपनी गोटा, खमन, दालवाड़ा, दही-वड़ा, ढोकला, इडली और डोसा के आटे के मिश्रण को पाउडर के रूप में बेचती है। जीएएएआर ने अपीलकर्ता की दलील को खारिज करते हुए कहा कि इंस्टेंट आटा मिक्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री प्रासंगिक जीएसटी नियमों के तहत शामिल नहीं है, जैसा कि सत्तू के मामले में है।

Positive Health Zone
Unique Wellbeing Center
Quantum Machine से
नाड़ी परीक्षण
HRV Technology, Based Health Analysis
वैदिक काल से ही हमारे वैद्य नाड़ी जांच के द्वारा हमारे स्वास्थ्य की जांच करते आ रहे है।
आज इक्कीसवीं सदी में नाड़ी जांच करना और भी सरल हो गया है,
Veda Pulse - Modern Nadi Vaidya
के माध्यम से।
Vedapulse® Assesses
- Prakruti vikruti analysis
- Dosha vata pita kapha and Subdosha balance.
- Agni & 7 dhatu balance.
- Balance of pancha mahabhuta.
- Ojas, tejas, prana analysis.
- Rate of biological aging
- Satva, rajas, tamas analysis.

"Pulse Of The Organs" Helps Forming Recommendations For Diet Plan Day Plan And Body Detox Plan With Personalised Lifestyle Modifications Recommendations.

किसानों और ग्रामीणों के सच्चे साथी बनेंगे 'दामिनी और मेघदूत'

मेघदूत एप्प से मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी और दामिनी एप्प बचाएगी आकाशीय बिजली के कहर से

रायपुर। किसानों और ग्रामीणों के दो सच्चे साथी अब हमेशा उनके साथ रहेंगे। एक उन्हें मौसम संबंधी जानकारी से लैस करेगा, तो दूसरा आकाशीय बिजली की कहर से बचाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही खेती-किसानी का काम-काज शुरू हो जाता है। किसान भाई मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए मेघदूत और आकाशीय बिजली से जनहानि और पशुहानि से बचाव के लिए दामिनी एप्प का सहारा ले सकते हैं।

भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इन दोनों एप्प को लॉन्च किया है। इसे गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से किसी भी एंड्राइड मोबाईल पर डाउनलोड किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को राजस्व विभाग और अन्य विभागों के मैदानी अमले के माध्यम से इन दोनों ही एप्प का प्रचार-प्रसार करने के साथ ही गांवों में मुनादी करने के निर्देश दिए गए हैं। खेती-किसानी के सीजन में किसानों के लिए मौसम की सटीक जानकारी आवश्यक होती है, इससे खेती-किसानी का काम-काज व्यवस्थित और सुचारू ढंग से करने में मदद मिलती है। मेघदूत एप्प के माध्यम से किसान भाई मौसम पूर्वानुमान जैसे तापमान, वर्षा की स्थिति, हवा की गति एवं दिशा इत्यादि की जानकारी मिलेगी, जिससे किसान अपने क्षेत्र की मौसम से संबंधित पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मानसून के दौरान ही आकाशीय बिजली की घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, इसके कारण अधिक संख्या में जन एवं पशु हानि की सूचनाएं प्राप्त होती है। इन घटनाओं में कमी लाने और लोगों को सचेत करने के लिए दामिनी एप्प तैयार किया गया है।

इस एप्प के माध्यम से 20 से 31 किलोमीटर के दायरे में आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान मिल जाएगा। इससे पशुहानि और जनहानि को रोकने में मदद मिलेगी।

ऐसे बनती है आकाशीय बिजली

जब ठंडी हवा संघनित होकर बादल बनती है तब इन बादलों के अंदर गर्म हवा की गति और नीचे ठंडी हवा के होने से बादलों में धनावेश (पॉजिटिव चार्ज) ऊपर की ओर एवं ऋणावेश (निगेटिव चार्ज) नीचे की ओर होता है। बादलों में इन विपरीत आवेशों की आपसी क्रिया से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। फिर धरती पर पहुंचने पर आकाशीय बिजली बेहतर चालक को तलाशती हैं, जिससे वह गुजर सके। इसके लिए धातु और पेड़ उपयुक्त होते हैं।

बिजली अक्सर इन्हीं माध्यमों से पृथ्वी में जाने का रास्ता चुनती है। इसलिए बरसात के दिनों में लोग बिजली के खंभों, पेड़ों और धातुओं से दूर रहना चाहिए तथा बिजली के उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें। जितना हो सके आकाशीय बिजली की स्थिति में मोबाइल का उपयोग नहीं किया जाए।

मीडिया के एजेंडे पर अब कौन ?

मजबूर सत्ता या मज़बूत जनता

श्रवण गर्ग

जनता का एक बड़ा वर्ग जांनने को उत्सुक है कि अब जब कि चुनाव सम्पन्न हो गए हैं, तमाम अनुमानों को अंगूठा बताते हुए नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भी शपथ ले ली है, सरकार की सेवा में समर्पण भाव से दिन-रात जुटे रहे टी वी चैनलों और अख़बारों की ज़िंदगी में भी कुछ फ़र्क़ पड़ेगा या सब कुछ पहले जैसा ही चलने वाला है ? किसी बड़े तूफान के गुज़र जाने के बाद जैसे लोगों की समझ में नहीं आता कि सामान कहाँ से बटोरना शुरू करें, तूफ़ानी चुनाव के बाद मीडिया को लेकर भी पाठकों और दर्शकों की हालत वैसी ही है।

उन्नीस अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में सम्पन्न हुई मतदान की प्रक्रिया, उसके साथ-साथ और पहले चला धुआँधार चुनाव.प्रचार, उसके पहले हुए दलों के बीच गठबंधन, टिकटों के बँटवारों से नाराज़ उम्मीदवारों द्वारा दल-बदल की रस्म अदायगी, चाचाष् नीतीश कुमार को लेकर बना नाटकीय घटनाक्रम सब कुछ किसी लम्बे टी वी सीरियल की तरह पाठकों-दर्शकों पर छाया रहा।

चुनावों के दौरान जनता टीवी.यूट्यूब चैनलों और अख़बारों के पन्नों के साथ वैसी ही चिपकी रही जैसा किसी समय रामायण, महाभारत और चाणक्य आदि धारावाहिकों के समय हुआ करता था। नौ जून की शाम राष्ट्रपति भवन परिसर में फि.ल्माए गए अंतिम दृश्य के बाद से लोगों को सूझ नहीं पड़ रही है कि अब अपना टाइम कैसे पास करेंगे ?

नागरिकों की बड़ी चिंताओं में इस बात का शुमार भी किया जा सकता है कि अपनी पहली दो पारियों में निरंकुश बहुमत का एकाधिकारवाद भोग लेने के बाद अगर किसी सरकार को तीसरी पारी में बैसाखियों पर साँसें गिनना पड़े तो उस दौरान मीडिया की भूमिका क्या होना चाहिए ? कहा जा रहा है कि पिछली दो पारियों की तुलना में तीसरी पारी में भाजपा को मिले कमज़ोर समर्थन के पीछे भी असली ताक़त 'गोदी मीडिया' की ही रही है। ख़ास करके हिंदी पट्टी में। इनमें टी वी, अख़बार और सोशल मीडिया सभी शामिल है। मीडिया की भूमिका अगर निष्पक्ष रही होती तो नतीजे काफ़ी चौंकानेवाले होते।

आपातकाल (1975) के दौरान मीडिया की भूमिका के बारे में लालकृष्ण आडवाणी ने टिप्पणी की थी कि (इंदिरा गांधी) सरकार ने तो मीडिया से सिर्फ़ झुकने के लिए कहा था पर वह घुटनों के बल रैंगने लगा। मोदीजी के दस सालों के राज के दौरान आडवाणी जी ने न तो कभी मीडिया के रेंगने को लेकर कोई टिप्पणी की और न ही स्वयं की भूमिका को लेकर। जिस तरह 'घोषित आपातकाल' के दौरान अधिकतर लड़ाई या तो जनता ने लड़ी थी या फिर मीडिया के उस छोटे से वर्ग ने जो सत्ता प्रतिष्ठान से नहीं डरा था, वैसी ही स्थिति पिछले दस सालों के दौरान अघोषित आपातकाल में भी थी।

मीडिया के लिए अपनी नई भूमिका पर विचार करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि जिस एक 'परिवार' और उसके नेता को पूरे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी द्वारा सबसे ज़्यादा निशाने पर लिया गया, वह चार जून के नतीजों के बाद जनता के बीच सरकार से ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरा है। पिछले चुनावों की तरह इस बार विपक्ष अपने हताहतों की गिनती में नहीं कर रहा है बल्कि सरकार पर नए हमले की तैयारी में जुटा है।

सवाल यह है कि चंद्राबाबू और नीतीश कुमार की कृपा से एन डी ए को जिस तरह का अस्थायी बहुमत मिल गया है वह अगर नहीं मिलता और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का दावा पेश करने क़ाबिल सीटें मिल जातीं तब भी क्या मीडिया हिंदू-मुस्लिम दंगलों के ज़रिए ही टीआरपी बढ़ाने में जुटा रहता या सार्थक बहसों के लिए नये मुद्दों की तलाश करता ?

दुनिया के प्रतिष्ठित मीडिया प्रतिष्ठानों के बारे में यही कहा गया है कि सत्ता में चाहे जो व्यक्ति या पार्टी रहे, वे हमेशा एक 'एडवर्सरी' या 'प्रतिपक्षी' की भूमिका में रहते हैं और उस पर गर्व भी करते हैं। कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें किसी एक दल को एकाधिकारपूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाए तो विपक्ष से बड़ी चुनौती मीडिया के सामने खड़ी हो जाती है।

लोकसभा चुनाव का नशा जैसे.जैसे कम होगा, बदली हुई जनता सरकार और मीडिया दोनों को ही कठघरों में खड़ा करने वाली है। पूछा भी जाने लगा है कि मीडिया अब क्या करने वाला है ? एक बात अभी से नज़र आने लगी है कि राजनीतिक तौर पर कमज़ोर होकर उभरे मोदी, मीडिया पर नियंत्रण को और कसने की कोशिश कर सकते हैं। वे क़तई नहीं चाहेंगे कि मीडिया राहुल गांधी और उनके नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के प्रति किसी भी तरह की उदारता दिखाए। तय मीडिया को करना है कि बदली हुई परिस्थितियों में भी वह किसके एजेंडे पर काम करने वाला है। वह एक कमज़ोर हुकूमत के या ताकतवर जनता के साथ खड़ा होना पसन्द करेगा।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए करेंगे काम: मुख्यमंत्री

हमने मोदी की गारंटी के वादे को पूरा किया, लोकसभा में जनता का मिला भरपूर आशीर्वाद

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुश्किल से 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में हम लोगों को कम काम करने का अवसर मिला इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। आचार संहिता लागू हो गई। लेकिन आचार संहिता लागू होने से पहले मात्र सौ दिनों में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के सभी प्रमुख वादों को प्राथमिकता से पूरा किया है। जिसका बेहतर परिणाम हमें लोकसभा में मिला। मोदी जी सहित हमारी सरकार पर भी लोगों का विश्वास बढ़ा है। आगामी समय में गारंटी के बचे हुए वादे को सांय-सांय पूरा करेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा के चुनाव में हमें छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया और चौथी बार हम लोगों ने सरकार बनाई। पहले की तीन बार की जो भाजपा सरकार थी, उससे भी ज्यादा आशीर्वाद भाजपा को मिला। 54 सीटें और 46ब से ज्यादा वोट पार्टी को मिला। जनता के भरोसे पर खरा उतरते हुए हमने 100 दिनों में मोदी की गारंटी के प्रमुख वादे को पूरा किया।

सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार में 18 लाख लोग पिछले पांच साल में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जी का भी कहना था कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती है, तो जो मुख्यमंत्री होगा वह सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का काम करेगा। मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी। 25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, सुशासन दिवस के अवसर पर हम लोगों ने 12 लाख से ज्यादा किसानों को 2 साल का बकाया का बोनस देने का काम किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' बताते हुए वादे के अनुरूप किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान को 3100 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने के वादे को पूरा करने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रति महीने एक-एक हजार के हिसाब से चार किश्त जारी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच, रामलला दर्शन योजना की भी शुरुआत उनकी सरकार ने कर दी है। 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी की भी शुरुआत करने और खरीदी के लिए 15 दिनों का समय तय करने की बात उन्होंने पत्रकारों को बताई।

नक्सलवाद के खिलाफ बोलते हुए विष्णु देव साय ने कहा कि पिछले 15 साल की हमारी भाजपा सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी और जब फिर से भाजपा की सरकार बनी तो केंद्र-राज्य के समन्वय से नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में और भी तेजी आई है। उन्होंने मीडिया के साथियों से आग्रह करते हुए कहा कि जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, नक्सलवाद जैसा लोग सोचते हैं, वैसा कुछ भी नही है। इसलिए छत्तीसगढ़ को ऐसी नजरों से बिल्कुल भी न देखें। केवल पांच जिलों में ही कुछ जगह पर नक्सलवाद है। इन क्षेत्रों में अभी तक लगभग 25 से ज्यादा सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं और इसका मतलब कैंप के 5 किलोमीटर के रेडियस में सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। नक्सली लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं।

श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारा बस्तर स्वर्ग है, जहां चित्रकोट वाटरफॉल से लेकर कुटुमसर गुफा और तीरथगढ़ जलप्रपात है। हमारा प्रयास है कि पर्यटन क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करें, जिससे आय का स्त्रोत बढ़े। छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार की कमी नहीं है।

लौह अयस्क भरपूर है, पूरा बैलाडिला का पहाड़ है। गोल्ड, डायमंड है, लिथियम भी मिला है। खनिज संपदा भरपूर है, 100 से अधिक वनोपज भी है, मेहनतकश किसान हैं। इसलिए सभी छत्तीसगढ़ वासी मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए काम करेंगे।

दिल्ली के पत्रकारों को बताया सांय-सांय का मतलब

विष्णु देव साय ने कहा कि मात्र 100 दिन में ही हमारी सरकार ने इतना काम किया, जिसका परिणाम हमें लोकसभा में बेहतर मिला। सांय-सांय काम हुआ तो यह ट्रेंड हो गया। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में इसका मतलब जल्दी-जल्दी होता है। हम जहां भी जाते हैं तो लोग सांय-सांय चिल्लाते हैं। क्योंकि हमने मोदी की गारंटी के प्रमुख वादे को सांय-सांय पूरा किया है और आगे भी सांय-सांय पूरा करेंगे।

भाजपा-आरएसएस में रार, किसके हाथ होगी बीजेपी की पतवार

लोकसभा चुनाव और मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के एक दिन के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सभी धर्मों को लेकर आये बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे है । भागवत ने मणिपुर हिंसा पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मणिपुर पिछले एक साल से शांति की राह देख रहा है। मणिपुर राज्य पिछले 10 साल शांत रहा, लेकिन अचानक से गन कल्चर फिर से बढ़ा, जो कलह वहां पर हुई। उसपर प्राथमिकता देकर विचार करना जरूरी है।

नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय समापन समारोह को संबोधित करने के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। सभी की पूजा का सम्मान करना है, ये मान कर चलना है कि हमारे जैसा उनका धर्म भी सच्चा है। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसमें दो पक्ष होने के कारण प्रतिस्पर्धा होती है। चूंकि यह एक प्रतिस्पर्धा है, इसलिए खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसमें एक गरिमा होती है। झूठ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने आगे कहा कि चूंकी जनता संसद में जाने और देश चलाने के लिए लोगों को चुनती है। लिहाजा वे सहमति बनाकर ऐसा करें , यह प्रतिस्पर्धा कोई युद्ध नहीं है। एक-दूसरे की जिस तरह की आलोचना की गई, इस तरह के अभियान चलाने से समाज में मतभेद पैदा होगा और विभाजन होगा। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आरएसएस जैसे संगठनों को भी इसमें बेवजह घसीटा गया। भागवत ने कहा कि तकनीक की मदद से झूठ को पेश किया गया, झूठ को प्रचारित करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ऐसा देश कैसे चलेगा ? विपक्ष को विरोधी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वे विपक्ष हैं वे एक पक्ष को उजागर कर रहे हैं। उनकी राय भी सामने आनी चाहिए। चुनाव लड़ने की एक गरिमा होती है, उस गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया. ऐसा करना जरूरी है क्योंकि हमारे देश के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। संघ प्रमुख का इशारा साफ़ था वो इस चुनाव में अजमाए गए चुनावी हथकन्डो का समर्थन नही करते . बरहाल 10 जून को नई सरकार के मंत्रियों को पोर्टफोलियो मिल गया . बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मोदी 3, कैबिनेट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ-साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मंत्री पद के शपथ लेने से पहले इस बात पर भी चर्चा छिड़ी हुई थी कि मनोहर लाल खट्टर या शिवराज सिंह चौहान को भाजपा अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है. लेकिन इन दोनों नेताओं के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ही सभी दावों पर विराम लग गया. ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के लिए कई नाम सामने आ रहे है इनमे से एक नाम डी. पुरंदेश्वरी का है जिन्हें स्पीकर बनाकर भाजपा डी. पुरंदेश्वरी तेलुगू देशम पार्टी (ञ्ष्ठक्क) के संस्थापक और दिग्गज नेता रहे एनटी रामाराव की बेटी हैं. 64 साल की पुरंदेश्वरी मौजूदा ञ्ष्ठक्क प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की साली हैं. आंध्र प्रदेश को बांटकर दो राज्य बनाने के मसले पर पुरंदेश्वरी कांग्रेस से नाराज हो गई थीं. तब उन्होंने कहा था कि जिस तरह कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य बनाने के लिए आंध्र प्रदेश का विभाजन किया है, उससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा है. 2014 को उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर ञ्ष्ठक्कज्वॉइन कर लिया. मौजूदा समय में वो आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष हैं. एक तीर से दो निशाना साधने की तैयारी में है.

एक और नाम जो चर्चा में है वह महाराष्ट्र से आने वाले विनोद तावड़े का है. जो वर्तमान में बिहार के प्रभारी महासचिव हैं. बीजेपी बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही. इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया था, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ज्यादातर देखने को मिला था.

महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा का चुनाव भी है. ऐसे में पार्टी ओबीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर खुद से छिटका हुआ वोट बैंक फिर से समेटने की कोशिश कर सकती है. तांवड़े माराठा समुदाय से भी ताल्लुक रखते हैं. पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र मराठा आंदोलन की वजह से अशांत रहा है. जगह-जगह केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए गए. ऐसे में विनोद तांवड़े यहां तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं. तांवड़े ने बीते कुछ दिनों में मोदी सराकार की योजनाओं का खूब प्रचार-प्रसार भी किया है. विनोद तावड़े पहले नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में कृषि के लिए अलग बजट की मांग की थी.

राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक और नाम जो इस समय चर्चा के केंद्र में है वह वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल का हैं. उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है. सुनील बंसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व प्रचारक रह चुके हैं. राजनीतिक रूप से इन्होंने कई बार खुद को साबित किया है.

एक नाम बीएल संतोष का भी है जो आरएसएस के बड़े प्रचारक भी रह चुके हैं वर्तमान में बीजेपी के संगठन महासचिव हैं परदे के पीछे रणनीति बनाने में माहिर बीएल संतोष को कुछ लोग बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बेहतर विकल्प मानते है लेकिन उनके लिए यह पद पाना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. क्योंकि 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उसके लिए राज्य बीजेपी का एक बड़ा वर्ग बीएल संतोष को दोषी मानता है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में एक और दावेदार राजस्थान से ओम प्रकाश माथुर हैं. छत्तीसगढ़ में हुए विधासभा चुनाव के लिए पार्टी ने उन्हें राज्य का प्रभारी बनाकर भेजा था. उस चुनाव में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी. 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओम माथुर ने सुनील बंसल के साथ मिलकर राज्य में बीजेपी की जीत की पटकथा लिखी थी. ऐसे कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही वह ओम माथुर के संगठन के तौर पर काम करने के कायल रहे हैं. उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बायां हाथ माना जाता है.

दक्षिण के राज्य तेलंगाना के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के लक्ष्मण भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौर में बने हुए हैं. फिलहाल वह बीजेपी के ओबीसी मोर्चा प्रमुख के पद पर हैं, ऐसे में बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दक्षिण के राज्यों में ओबीसी वोट बैंक को साध सकती है. आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी गठबंधन की सरकार में सहयोगी है, ऐसे में अब पार्टी की नजर तेलंगाना पर भी होगी.

के लक्ष्मण की पहचान यहा है कि वे शांत और आक्रमक दोनों तरीके से पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं. हालांकि तेलंगाना के बाहर उन्हें कोई नहीं जानता है, जो उनकी संभावित उम्मीदवारी के खिलाफ जाता है.

गठबंधन की सरकार मजबूरी में कितनी मजबूती

एनडीए के सर्व सम्मति से नेता चुने जाने के बाद नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर देश के दूसरे नेता हो गए है जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे है . दो कार्यकाल में पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने वाले नरेन्द्र मोदी को गठबंधन धर्म निभाने की कड़ी चुनौतियां आएँगी. प्रमुख रूप से टीडीपी और जेडीयू के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय दलों की . दरअसल भारत जैसे बड़े देश में राज्यों की अलग-अलग समस्याएं और जरूरतें हैं. उनकी अलग-अलग सांस्कृतिक-भाषायी बनावट है. ऐसे में उनके स्थानीय मुद्दे उठाने वाली पार्टियां अहम हो जाती हैं. यही वजह है कि आज भाजपा और कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टियों के बीच भी क्षेत्रीय पार्टियां दिल्ली में सत्ता के ताले की चाबी बनी हुई हैं.

क्षेत्रीय पार्टियों की केंद्र में भूमिका पर कई बहस होती रही हैं. कुछ लोग इन्हें ताकत पर लगाम लगाने की भूमिका के चलते ताकत के विकेंद्रीकरण को लोकतंत्र के लिए जरूरी और बेहतर बताते हैं. वहीं दूसरी तरफ का मत इन्हें कड़े फैसले ना होने, या फैसले में देरी होने के लिए जिम्मेदार बनाते हैं, तो वहीं गठबंधन धर्म सभी पार्टियों में एकमत बनाने के लिए बाध्य करता है.

खैर आपका जो भी मत हो मगर सच्चाई यही है कि भारत में बीते 35 साल, मतलब 1989 से लगातार गठबंधन की सरकारें ही बनी हैं. भले 2014 और 2019 में भाजपा को दरकार ना रही हो, फिर भी गठबंधन जारी था और आज 2024 में फिर गठबंधन की जरूरत केंद्र में है जिसकी नीव 1977 में पड़ी थी. जब 1975 में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के बाद, 1977 के चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों की जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में लामबंदी शुरू हुई, लेकिन इसे गठबंधन कहना उतना सही नहीं होगा. क्योंकि 1977 के चुनाव में अलग-अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों का जनता पार्टी में विलय किया गया था. चुनाव में जनता पार्टी को 295 सीटें मिलीं. जबकि कांग्रेस 154 सीटों पर सिमट गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार देश को केंद्र में एक गैर-कांग्रेसी सरकार मिली.

सही तौर पर यदि गठबंधन की राजनीति को देखे तो वह 1984 से 1989 का दौर था . जब देश में उग्रवाद पनप रहा था , पंजाब में विद्रोह, श्रीलंकाई गृह युद्ध जैसी चीजों में सरकार फंसी थी . इसी दौर में 'कमंडल' राजनीति की नींव पड़ रही थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अपने मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ 36 का आंकड़ा बन रहा था जो तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद वीपी सिंह की कांग्रेस से विदाई के साथ और तेज हो गया.

अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान के साथ वीपी सिंह ने पहले जनमोर्चा बनाया, जो बाद में जनता पार्टी के बचे-हुए छोटे-छोटे हिस्सों के साथ मिलकर जनता दल बना.

सत्ता में आने वाला पहला राष्ट्रीय गठबंधन 1988-89 में नेशनल फ्रंट जिसमें जनता दल के साथ एनटी रामाराव की टीडीपी करुणानिधि की डीएमके, कांग्रेस सोशलिस्ट समेत अन्य पार्टियां शामिल थीं. इसे लोगो ने थर्ड फ्रंट का नाम दिया था. इस चुनाव में कांग्रेस की सीटें पिछले चुनाव में 413 से कम होकर सीधे 197 हो गईं थी और नेशनल फ्रंट143 सीटें लेकर आया था. सरकार को 85 सीटो वाली BJP और कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन का 33 सीटो वाला वाम मोर्चा ने बाहर से समर्थन दिया.

नवंबर 1990 में नेशनल फ्रंट की आपसी राजनीति के बीच, समाजवादी जनता पार्टी के चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने. 1991 में कांग्रेस ने राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में फिर से सत्ता में वापसी की और नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने. तब AIADMK समेत अन्य दलों ने सरकार को समर्थन दिया था.

फिर आया 1996-97 का वर्ष जब संयुक्त मोर्चा बना और एक साल में देश को मिले दो प्रधानमंत्री. इस चुनाव में BJP देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सरकार बनाने का दावा किया. प्रधानमन्त्री बने अटल बिहारी वाजपेयी लेकिन बहुमत जुटा नहीं पाए और 13 दिन के बाद यह अल्पमत की सरकार गिर गई. इसके बाद कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट को बाहर से समर्थन देकर सरकार बनवाई. और HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने. एक साल चली सरकार में, देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री बने. लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापसी के चलते सरकार गिर गई और 1998 में दोबारा आम चुनाव हुए.

और यहाँ से शुरुआत हुई वर्तमान गठबंधन राजनीति की अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में NDA (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस/राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन) का गठन किया गया. चुनाव में BJP 161 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि NDA ने 182 सीटें जीतीं. बाद में AIADMK जैसी पार्टियां BJP के साथ आईं और अटल बिहारी प्रधानमंत्री पुन: प्रधानमंत्री बने. TDP ने बाहर से समर्थन दिया. लेकिन 10 महीने बाद ही AIADMK द्वारा समर्थन वापसी के चलत 1 वोट से यह सरकार गिर गई और 1999 में फिर से आम चुनाव हुए.

1999 में कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस की सीटें कम होकर 114 रह गईं. NDA को कुल 270 सीटें मिलीं, जिसने कुछ अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई. ये पहली गैर कांग्रेस सरकार थी, जिसने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया.

फिर आया 2004 का चुनाव , जिसमे NDA को बड़ा झटका लगा था. इंडिया शाइनिंग का थीम चलाने वाली BJP 138 सीटों पर सिमट गई और NDA कुल 182 पर. जबकि कांग्रेस को 145 सीटें मिलीं. अब कांग्रेस ने सरकार बनाने की कोशिश शुरू की, वामपंथी पार्टियों के साथ-साथ SP, BSP और केरल कांग्रेस जैसी पार्टियों को साथ लाया गया और इस गठबंधन नाम पड़ा UPA या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन.

2009 में भी यही गठबंधन चुनाव जीता. 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में भी इसी गठबंधन ने NDA से दो-दो हाथ किए. और इस तरह भारत की राजनीति आज गठबंधनों की अनिवार्यता पर आ टिकी है.

दो–दो मंत्री छह विधायक फिर भी हार गई भाजपा

छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस मात्र एक सीट जीत पाने में ही कामयाब हुई. वो सीट रही कोरबा की. प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट कही जाने वाली राजनांदगांव लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 44 हजार से ज्यादा वोटो से चुनाव हार गए . ऐसे मे सवाल उठने लगा है कि जो कद्दावर नेता चुनाव हार गए आने वाले दिनों में पार्टी में उनकी भूमिका क्या होगी.

लोकसभा चुनाव के नतीजो ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दिया है प्रदेश के 11 में से सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस के हिस्से आई.जिले के बाहर जाकर दूसरी लोकसभा सीटों से दावेदारी करने वाले सभी दिग्गजों को हर का सामना करना पड़ा है. प्रदेश की राजनीति इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही जिले के चार बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए दूसरे जिले में भेजा गया हो इनमें से कांग्रेस ने अपने तीन बड़े नेताओं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव पूर्व मंत्रि ताम्रध्वज साहू को को महासमुंद पर और विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर सीट से प्रत्याशी बनवाया था तो भाजपा ने अपनी सबसे कददावार और तेज तर्रार महिला नेत्रीपूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय को कोरबा लोकसभा से उम्मीदवार बनाया. लेकिन वह उसे क्षेत्र में जाकर के वहां की जनता पर अपना विश्वास नहीं बना पाए और जनता ने उन्हें बाहरी प्रत्याशी बताते हुए नकार दिया. कांग्रेस प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में इतना उलझ गए थे कि उन्हें दुर्ग की सुध भी न रही.

छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस मात्र एक सीट जीत पाने में ही कामयाब हुई. वो सीट रही कोरबा की. प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट कही जाने वाली राजनांदगांव लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 44 हजार से ज्यादा वोटो से चुनाव हार गए . ऐसे मे सवाल उठने लगा है कि जो कद्दावर नेता चुनाव हार गए आने वाले दिनों में पार्टी में उनकी भूमिका क्या होगी. छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भूपेश बघेल सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं और यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें राजनांदगांव से टिकट दिया था चर्चा है कि बघेल की और उनकी टीम को टिकट वितरण के पहले ही क्षेत्र में तैयारी करने के निर्देश दिए गए थे साथ ही बघेल ने पूरा चुनाव अपनी स्टाइल में लड़ा इसलिए चुनाव के बाद अब उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगे हैं. भूपेश बघेल को प्रियंका गांधी का करीबी भी माना जाता है उम्मीद थी अगर वह चुनाव जीत जाते तो राष्ट्रीय स्तर पर उनके कद में बढ़ोतरी होती परिणाम के बाद फिलहाल यह मुश्किल तो नजर आने लगा है. छत्तीसगढ़ में साहू समाज के सबसे बड़े नेताओं में शुमार पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को साहू बाहुल्य सीट महासमुंद से टिकट दी गई थी लेकिन उन्हें यहां से करारी हार का सामना करना पड़ा चुनाव प्रचार के दौरान महासमुंद भी एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस के किसी बड़े नेता की सभा नहीं हुई जिसकी चर्चाएं आम है. चर्चा उनकी सेहत और महासमुंद के परिणाम के बाद यह भी हैँ कि भविष्य मे उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी जाएगी या नहीं.जांजगीर चंपा के सीट पर भारतीय जनता पार्टी की कमलेश जांगड़े से लगभग 60000 वोटो से चुनाव हारने वाले कांग्रेस सरकार मे मंत्री रहें कददावार नेता शिव डहरिया को लेकर के भी पार्टी के भीतर खाने में काफी चर्चा चल रही है कयास हैँ कि डहरिया का यह अंतिम चुनाव भी हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी डहरिया विधानसभा में बुरी तरह से हार गए थे. बिलासपुर सीट ने इस बार भी कांग्रेस को इस बार भी कांग्रेस को निराश किया है यह सीट पिछले 40 साल से भाजपा का गढ़ बनी हुई है तमाम कोशिशो के बावजूद कांग्रेस यहां अपना परचम फहराने मे कामयाब नहीं हुई, अंदर खाने गुफ्तगू है कि बघेल नहीं चाहते थे कि यादव यहां पर चुनाव लड़े लेकिन इस सीट पर यादव समाज की बहुलता को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उन्हें यहां से मौका तो दिया था मगर देवेंद्र कुछ कमाल नहीं कर पाए हालांकि यह उनका पहला चुनाव था

जो वो हार गए ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां में तो कमी नहीं आयेगी लेकिन साख पर असर जरूर पड़ेगा. छत्तीसगढ़ की सबसे ऐतिहासिक सीटों में रही है रायपुर जहां से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय कांग्रेस की ओर मैदान में थे. पार्टी ने उन्हें अब तक कुल तीन बार विधायक और एक बार सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दिया जिसमें से वह केवल एक बार कल 2018 में ही चुनाव जीत करें एमएलए बने थे बाकी तीन चुनाव वो हार गए. रायपुर पश्चिम से भी विकास को लीड नहीं मिली वह वहां से लगभग 38000 वोटो से पीछे थे यही नहीं एक भी राउंड में वह बृजमोहन को पीछे कर लीड नहीं ले पाए ऐसे में चर्चा है कि इस बार चुनाव परिणाम के बाद उनकी मुश्किलें शायद कुछ बढ़ सकती है .

बात तो भाजपा नेताओं की भी होनी चाहिए 11 की 11 सीट जीतने का दावा करने वाली भाजपा से 1सीट न जीत पाने की चूक कहाँ हो गई. चर्चा तो कोरबा लोकसभा की होनी ही चाहिए जहाँ से दो दो मंत्री होने के बावजूद कोरबा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनाव हार जाती है. बात तोउठनी इन मंत्रियों का उनके क्षेत्र में कितना असर है बात इस पर भी होनी कि प्रदेश में 12 मंत्रियों में से 11 चुनाव जीतने की भूमिका में थे.. एक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को छोड़ दे जो खुद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो सीएम, डिप्टी सीएम समेत इन 11 मंत्रियों ने 11 लोकसभा सीट जीतने का जो स्वप्न देखा था उसको सच करने में कितना दम लगाया . बात तो होनी चाहिए कि विधानसभा क्षेत्र कोरबा से लखनलाल देवांगन विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी इसी लोकसभा के अंतर्गत आता है मनेंद्रगढ़ की विधानसभा जहां से श्याम बिहारी जायसवाल विधायक है और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं. कोरबा लोकसभा के अंतर्गत आठ विधानसभा सीट आती है जिनमें से छह विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है प्रश्न यही है कि फिर इस सीट पर चूक कहां से हो गई दो–दो मंत्री छह विधायक से एक सांसद जीता पाने में नाकाम क्यों हो गए? इस लोकसभा के लिए मुझे एक मशहूर शेर याद आता है कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था जो यहां बिल्कुल फिट बैठ रहा है सरोज पांडे ने इस इलाके के दौरा करने सभाएं लेने लोगों को अपने बोलने की कला से अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी मगर और बाकी स्थानी नेता उनके साथ पसीना बहाते कम ही दिखे थे.

क्या कंगना पर हमला एक साजिश है जलता पंजाब बनाने की

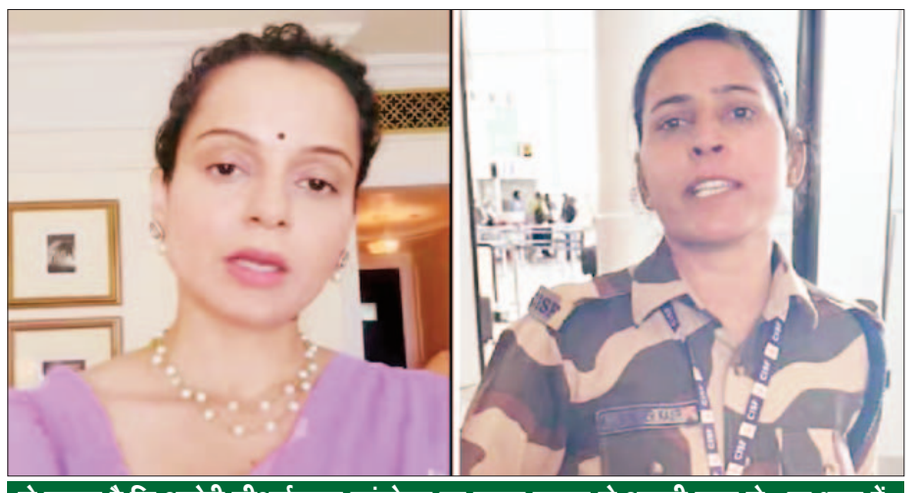

हो सकता है कि आरोपी सीआईएसफ कांस्टेबल का गुस्सा जायज हो आपकी नजर से, पर ध्यान दें वह देश की ऐसी सुरक्षा एजेंसी का हिस्सा है जहां पर इस तरह के गुस्से को जगह नहीं दी जा सकती. ये एजेंसिया देश के सभी एयरपोर्ट और मेट्रो जैसी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा देखती है. कुलविंदर कौर के गुस्से को जायज बताना वाले ध्यान रखें की आपके ये विचार आग से खेल करवाने जा रहे हैं. इस प्रकार का अतिवाद, आतंकवाद के लिए जगह बनता है शायद यही कारण है कि एक वर्ग यह बात कर रहा है कि इस तरह की विचारधारा को सिर उठाने के पहले कुचल देने की जरूरत है.

देश में जितनी चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर के हो रही है, नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने को लेकर हो रही है उतनी ही चर्चा कंगना रनौत के थप्पड़ कांड की भी हो रही है इस पर बॉलीवुड से कई सेलिब्रिटीज ने रिएक्ट भी किया है कुछ कंगना के सपोर्ट में अपनी बात रखी है तो कुछ ने उनके विरोध पर भी. सिंगर विशाल डडलानी ने कहा कि यदि सीआईएसफ कांस्टेबल कुलविंदर को नौकरी से निकाला जाता है तो हम उसे अपने यहां पर नौकरी देंगे. तो उधर अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी ने × पर लिखा कि मेरे दिल में कंगन के लिए कोई प्यार नहीं है लेकिन मैं अपने आप को उन लोगों के समूह में शामिल नहीं कर सकती जो उन्हें थप्पड़ मारे जाने का जश्न मना रहे हैं अगर सुरक्षा कर्मी ही कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा. इसी तरह रामगोपाल वर्मा, अमन वर्मा, अनुपम खेर सहित कई अन्य सितारे भी इस घटना को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं. लेकिन बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार अभी भी मौन है कोई भी कंगना रनौत की फोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं कर रहा है कोई एक्स पर ट्वीट नहीं कर रहा है वे लोग कहां चले गए जो रफा के बारे में बड़ी–बड़ी पोस्ट लिख रहे थे इजरायल का विरोध कर रहे थे फिलिस्तीन के ऊपर हुये हमले पर. क्या इन लोगों को केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिलिस्तीन के हमले दीखते हैं.यहां पर जो हमले होते हैं वही दिखाई नहीं देते, वहीं पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा इनको दिखाई पड़ती है हमारे भारत में होने वाली हिंसा पर इनसे कुछ नहीं बोला जाता. एक मशहूर अभिनेत्री को खुले आम एक एयरपोर्ट पर एक कर्मचारी द्वारा थप्पड़ मारा जाता है तो बॉलीवुड को यह दिखाई नहीं पड़ता है. जब एक सांसद के ऊपर हमला होता है तो किसी को भी भारत के लोकतंत्र के खतरे में जाने की चिंता नहीं होती है. इन लोगों को तब भारत असुरक्षित नहीं लगता.क्या यह चिंता इसलिए नहीं होती कि वह अभिनेत्री, वह महिला किसी एक विशेष कौम से संबंध नहीं रखती थी.

हो सकता है कि आरोपी सीआईएसफ कांस्टेबल का गुस्सा जायज हो आपकी नजर से, पर ध्यान दें वह देश की ऐसी सुरक्षा एजेंसी का हिस्सा है जहां पर इस तरह के गुस्से को जगह नहीं दी जा सकती. ये एजेंसिया देश के सभी एयरपोर्ट और मेट्रो जैसी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा देखती है. कुलविंदर कौर के गुस्से को जायज बताना वाले ध्यान रखें की आपके ये विचार आग से खेल करवाने जा रहे हैं. इस प्रकार का अतिवाद, आतंकवाद के लिए जगह बनता है शायद यही कारण है कि एक वर्ग यह बात कर रहा है कि इस तरह की विचारधारा को सिर उठाने के पहले कुचल देने की जरूरत है.

क्या कंगना को मारा गया थप्पड़ एक मामूली घटना है या आने वाले किसी बड़े साजिश की ओर संकेत दे रही है. जिस तरह उसे थप्पड़ मारा गया वह उसके मारने की स्टाइल खालिस्तान समर्थको की स्टाइल से मिलती है. कंगना कहती है कि जब मैं उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने नज़रें फेर ली और उसे तरफ मुख़ातिब हुई जिधर मोबाइल के द्वारा वीडियो शूट किया जा रहा था. महिला कांस्टेबल ने कहा था कि वह किसान आंदोलन के समय बैठी महिलाओं के खिलाफ कंगना द्वारा दिए गए विचारों से वो नाराज थी वह किसान कानूनो के निरस्त होने की वजह से भी नाराज थी इसलिए उसने कंगना राणावत को थप्पड़ मारा.

मगर यहां एक बात गौर करने की है किसान आंदोलन 2020 में हुआ था 4 साल लगे उसे घटना का बदला लेने के लिए इस कांस्टेबल को जबकि कंगना राणावत इस एयरपोर्ट से कई बार गुजरी होगी और महिला कांस्टेबल की वहां पर ड्यूटी भी लगी होगी, फिर 4 साल बाद ऐसी घटना क्यों की गई है तो थोड़ा अब इस राजनीतिक परिदृश्य को भी समझ लीजिएगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह छोटी–मोटी कोई घटना नहीं है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसका इशारा किया गया है. इस लोकसभा चुनाव के परिणाम पर अगर आप गौर करेंगे तो दो महत्वपूर्ण चीज हुई है पहला खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल जिस पर यूँ ए पी एल लगा हुआ है, जो जेल में बंद है,वह चुनाव जीत जाता है जेल के अंदर से. यानी कि पंजाब में कहीं ना कहीं खालीस्तानी समर्थकों की संख्या बढ़ रही है इस बात को तब और बल मिलता है जब महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर को आतंकी पन्नू ने सपोर्ट कर दिया खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने सीआईएसफ की महिला कांस्टेबल की तारीफ की है उसने कहा कि कंगना को थप्पड़ मारने से वह खुश है और इसके लिए वह महिला कांस्टेबल को .10000 यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 8 लख रुपए इनाम देने की घोषणा करता है. अब इस बात पर जरा भी संदेह नहीं किया जा सकता कि पंजाब के हालात अब किस बेहद नाजुक दौड़ से गुजर रहे हैं.

एक बार फिर से इस राज्य में जिस तरह से अलगाववाद फन फैला रहा है वह कभी भी पंजाब को उसके इस खूनी दौर पर वापस बुला सकता है जो 80 के दशक में हुआ करता था.

इस घटना के बाद ही सिख नेता और खालिस्तानी आंदोलन के संस्थापको में से एक रणजीत सिंह खालसा ने इसे जायज ठहराते हुए कहा कि कुलविंदर सिंह कौर महान योद्धा महिला है.उसने कहा कि कुलविंदर ने रनोत को थप्पड़ मार कर सिख समुदाय और सिख परंपराओं की लाज रखी है वह अब सिर्फ सीआईएसएफ के निलंबित सिपाही नहीं बल्कि पूरे सिख समुदाय की बेटी बन गई है.

सोशल मिडिया पर जिस तरह के पोस्टर आ रहे हैं अन्य मीडिया में आ रहे हैं इसे देखकर तो लगता है कि आने वाले समय में पंजाब के साथ समुचा देश काफी तकलीफ के दौर में गुजरेगा जैसा की 80 के दशक में हुआ करता था. यहां से मुझे कुछ घटनाये याद आती है जब इंदिरा गांधी को 1984 में उनके ही दो सुरक्षा कर्मियों ने गोलियों से भून डाला था. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब श्रीलंका के दौरे पर गए थे तो गॉड ऑफ ऑनर दिए जाते समय उनपर एक गार्ड के द्वारा उनपर बंदूक से हमला किया गया था,जिसमे वो बाल बाल बचें थे. और 1991 में इसी तरह एक लिट्टे आतंकवादी ने उन पर आत्मघाती हमला करके हत्या कर दी थी. इसी तरह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की भी हत्या कर दी गई थी एक आत्मघाती हमले में. ऐसी बहुत सारी घटनाएं और काफी दर्दनाक घटनाएं रही है जब सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके खुद के गार्ड द्वारा ही हमला किया गया हो, ऐसी घिनौनी हरकतें की गई थी. मैं यहां पर सिस्टम की भी बात करूंगा जहाँ मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई देती है.होता यह है कि जिन भी कर्मचारियों को यहां रखा जाता है सुरक्षा के रूप में एक बार रखने के बाद उनका जो टेस्ट वगैरह होता है मेडिकल टेस्ट होता है मानसिक परीक्षण होता है उसके बाद दोबारा कभी नहीं किया जाता लंबे समय तक ड्यूटी करते रहते हैं क्या जरूरी नहीं है कि उनकी समय–समय पर रिफ्रेश करते रहना चाहिए कि वह किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं इनका मेंटल स्टेटस कैसा है उनके विचारों में क्या तब्दीलियां आ रही है उनकी भावनाएं किस तरह से परिवर्तित हो रही है उनकी काउंसलिंग करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए. क्या इनका बैकग्राउंड चेक नहीं होना चाहिए कि वर्तमान में ये किन–किन लोगों के साथ में जुड़ रहें है इनकी बातें किसके साथ हो रही है यह फोन पर अधिकतर किसके संपर्क में है. हमने आफ्टरनून ब्लू स्टार का वह दौर भी देखा और सुना है कि किस तरह सेना के कुछ अधिकारी उस समय लगभग बगावत पर उतर आए थे. तो वर्तमान में हुई इस घटना को भी पास्ट से सीखते हुए आने वाले भविष्य की किसी चेवतानी के रूप में भी देखना चाहिए. जब इंदिरा गांधी के एक हत्यारे का बेटा सरबजीत सिंह खालसा चुनाव जीत जाता है तो क्या यह नहीं लगता कि पंजाब में अब कुछ बहुत गड़बड़ होने जा रहा है. ऐसा नहीं है कि यह लोग पहली बार ऐसे चुनकर आ रहे हैं याद रखिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान जब अपनी संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा सीट को छोड़ते हैं तो वहां से एक पूर्व आई पी एस जिन्हे एक ख़ालिस्तानी समर्थक, एक अलगाववादी नेता के रूप में पहचना जाता है मेंबर आफ पार्लियामेंट चुनकर आता है.

ध्यान देने की बात यह है कि इन सब के जो समर्थन देते है, इन लोगों को जो फंडिंग मिलती है, वो आका बैठते हैं अमेरिका में कनाडा में या अदर यूरोपियन कंट्री में. जब ऐसे लोग हमारे यहां सांसद चुनकर के आते हैं तो इनके फॉलोर्स और बढ़ जाते हैं.तब उस देश के भारतीय दूतावास के सामने खड़े होकर धरना प्रदर्शन करते हैं तख्तीयाँ लेकर खड़े जाते हैं,भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रध्वज को अपमानित करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ते.ये जितने भी आतंकवादी है, अलगाववादी है, यह पश्चिमी देशों के लिए हीरो होते हैं वह इन्हें भारत के खिलाफ एक हीरो के रूप में प्रस्तुत करते है. इन देशों को भारत की बढ़ती ताकत, भारत के बढ़ते स्टेटस बर्दाश्त नहीं होती.

अब जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं अपनी गठबंधन सरकार के साथ में यानी एनडीए 2 की तब नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी सरकार के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की सुरक्षा की.मोदी के पुराने कार्यकालों को देखकर के देश की जनता को कोई शंका नहीं होती है क्योंकि सबने देखा हैं कि वे किस तरह मुंह तोड़ जवाब देते हैं ऐसे लोगों को जो भारत में आतंकवादी संगठनों को पनाह देने की कोशिश करते हैं हमने देखा है किस तरह हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने घर में घुसकर के ऐसे लोगों को जवाब दिया है. यदि आप इस चुनाव पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विदेशी ताकतों ने किस तरह से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सरकार ना बनने,प्रधानमंत्री न बनने के लिए क्या–क्या हथकंडे नहीं अपनाये थे. लेकिन इन लोगों की सारी कोशिसे सारी साजिशे फेल हो गई. यह उसी का एक असर हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में दिखाई दे रहा है यह थप्पड़ कांड भी इसी गुस्से का, इसी फ्रास्टेशन का एक परिणाम है. थप्पड़ घटना की जांच शुरू हो चुकी है.

घटना आज के बाद ही पता चलेगा कि ऐसी घटना क्यों घटी, महिला कांस्टेबल गिरफ्तार हो गई है उसे निलंबित कर दिया गया है इंक्वारी हो रही है लेकिन प्रश्न केवल यह है कि 2020 की घटना और उस दौरान दिए गए बयान का बदला 2024 में क्यों? तब क्यों जब वह महिला भारत की एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट चुन ली जाती है? इसलिए लगता है कि आने वाला समय आतंकवादी और अलगाव वाद को बढ़ाने वाला हो सकता है. कंगना के हमले के पीछे कोई गहरी साजिश तो है जिससे एक बार फिर जल सकता है पंजाब.

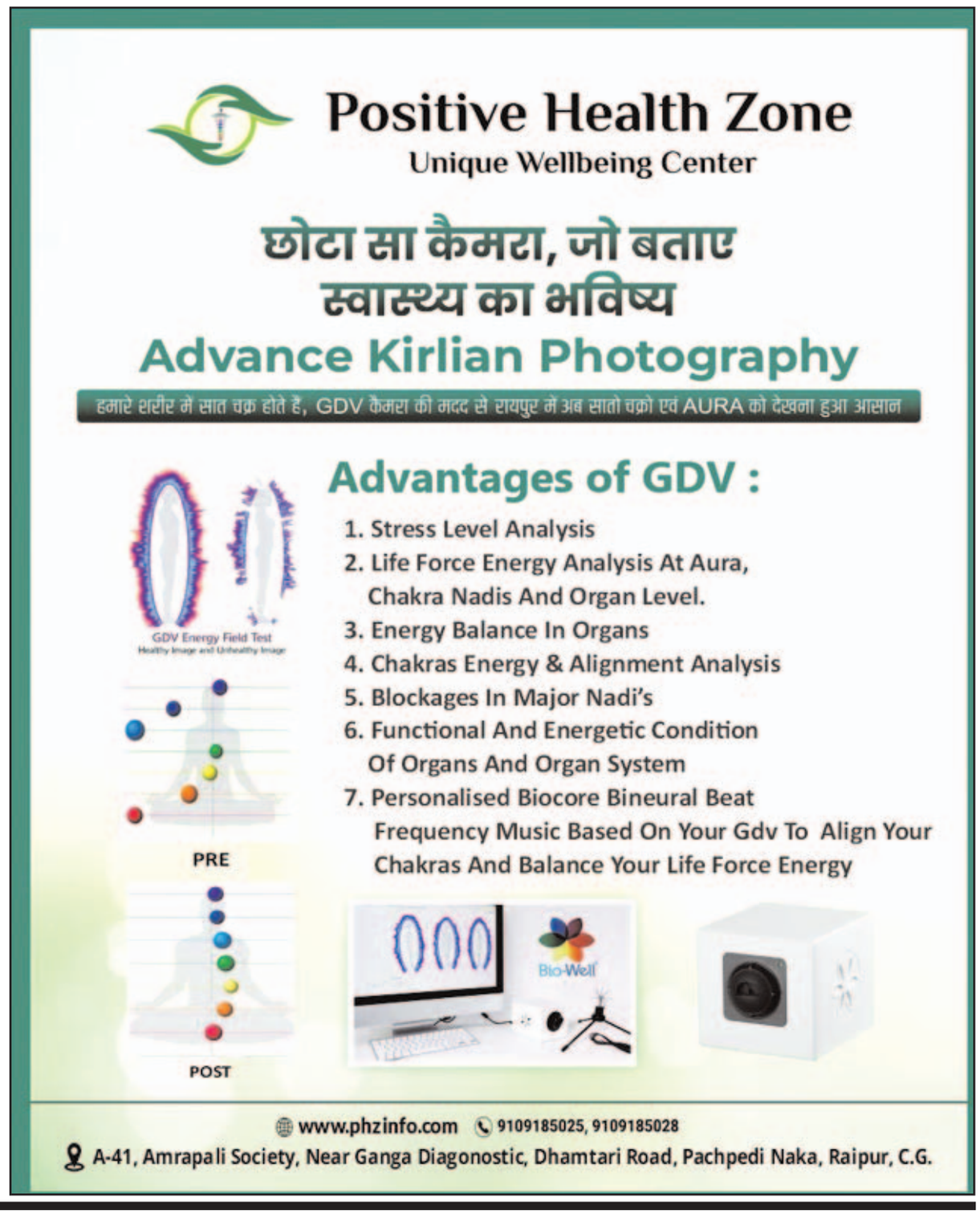

पहले बताया पाक साफ, अब कहते हैं गड़बड़ी हुई

4 जून 2024 को जब देश में लोकसभा के परिणाम आ रहे थे तभी एक और परिणाम आया . रिजल्ट था देश के दुसरे सबसे बड़े और कठिन एग्जाम नीट का. मेडिकल कॉलेज प्रवेश के इस एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद से ही सोशल मीडिया में तहलका मच गया. एक स्कैम होने की शंका के कई पोस्ट वायरल होने लगे .

नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 14 जून को जारी होने वाला था लेकिन अचानक बिना किसी सूचना के एनटीए 4 जून 2024 को इसे जारी कर दिया इसके बाद उम्मीदवारों सहित कई लोगों ने इस पर सवाल करने शुरू कर दिए सोशल मीडिया में करीब सभी प्लेटफार्म पर नीट यूजी 2024 का रिजल्ट खूब ट्रेंड कर रहा है एग्जाम में शामिल होने वाले कई सारे स्टूडेंट ने नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को एक स्कैम बता रहे हैं. उनका मानना है कि नीत यूजी रिजल्ट में घोटाला किया गया है इसलिए इसे रद्द कर देना चाहिए उम्मीदवारों की मेहनत और भविष्य के साथ एक गेम हो गया है उम्मीदवार को कहना है कि एनडीए एग्जाम और रिजल्ट दोनों को रद्द करके फिर से एग्जाम का आयोजन करना चाहिए क्योंकि लाखों स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है लेकिन सवाल यह है कि आप में कितनी सच्चाई है समझते हैं नीत रिजल्ट स्कैम के मामले को कुछ विस्तार से

दरसाल सोशल मीडिया पर रिजल्ट के पीडीएफ की एक फोटो वायरल हो रही है इसमें टॉपर की लिस्ट पर भी सवाल खड़े किए जा रहे

हैं जिसमें सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक की सीट रोल नंबर नाम मार्क्स और रंक के साथ गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है आरोप है कि जो रोल नंबर शामिल है वह सभी रोल नंबर एक ही केंद्र के या उनके आसपास के हैं साथ ही अधिकतर उम्मीदवारों के नाम के साथ उनके सरनेम गायब है. 8 में से 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक 2 को 719 718 अंक मिले हैं. एनटीए का कहना है कि एनसीआरटी टेक्सबुक और ग्रेस मार्क देने की वजह से टापरो की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.

लोचा तो है कहीं न कही कुछ गडबड तो है जो इते लोगो को 720 में से 720 मिले हैं . कई एस्परेंट की ख्वाहिश होती थी कि उन्हें एम्स दिल्ली मिलना चाहिए जो उसकी मेडिकल का सबसे टॉप कॉलेज कहलाता है अब 67 स्टूडेंट में से किन किन को मिलेगा जिन्होंने 720 मार्क्स में 720 लाए हैं . अलग अलग और मजेदार लॉजिक आ रहा है कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कई बार एग्जाम दिया होगा नीट का उन्हें प्राथमिकता मिलेगा . तो भाई प्रेशर की क्या गलती है पहले मना कर देते की फ्रेशर जो होंगे उन्हें एम्स दिल्ली नहीं मिलेगी. कुछ कहते हैं कि पर्ची उठा करके तय करेंगे यानी यहां छात्रों का लक काम करेगा. मतलब इतनी सारी मेहनत, एग्जाम का प्रेशर एग्जाम सेंटर में बैठेने का प्रेशर और उसके बाद लक काम करेगा.

यह तो बात हो गई उनकी हुई जिनको 720 मिले हैं बाकी और भी हैं यार गवर्नमेंट कॉलेज का क्या हाल रहेगा . जरा सोचिए कि एक ही नंबर पर कितने सारे बच्चे आएंगे जब 720 में 67 हैं . एक एग्जांपल देखिए अगर 680 मार्क्स किसी को मिले हैं मैं वह लिस्ट देखता कि उनके रैंकिंग कितनी होगी तो इस रैंक में यानी 680 पाने वाले बच्चे कुल 8453 से लेकर के 9513 तक की रैंक में है यानी कुल 1000 बच्चे हैं जिन्हें 680 नंबर मिले हैं . खत्म ऑल इंडिया की और जो अच्छे सरकारी इंस्टिट्यूट है सरकारी मेडिकल कॉलेज है वह तो 680 में भर गए. एनटीए कहता है कि हम पेपर को हाई स्कोरिंग बना रहे हैं सरल बना रहे हैं कोचिंग संस्थान के बढ़ते कंपटीशन को रोकने के लिए , अरे क्या फर्क पड़ जाएगा इस तरह अगर आप सरल कर देंगे , कंपटीशन को इतना सरल कर देंगे अब जरा सोचिए यार की एक एवरेज पढ़ाई करने वाला लड़का और अधिक मेहनत करने वाला लड़का दोनों बच्चे लगभग बराबरी के आगे खड़े हो जा रहे हैं,तो क्या हुआ इससे, अब इससे यह हुआ है कि 650 मार्क्स पाने वाले कुल 30000 रैंक , क्या कंपटीशन है मार्क्स तो ला लिया ,हाई स्कोर भी कर लिया , खुश हुआ बच्चा. लेकिन रैंक देखकर के क्या होगा जब उसे मनपसंद सरकारी कॉलेज इतने नंबर लेने के बाद भी नहीं मिलेगा.

इसीलिए तो इस स्कैम कहा जा रहा है स्कैम क्यों ना बोले जब नीट अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट ओपन होने की डेट लिखता है 14 जून तो प्रश्न उठेगा ही कि 14 जून को आने वाला रिजल्ट 4 जून को कैसे आ जाता है. घोटाले की स्मेल तो यहीं से आ रही थी क्योंकि 4 जून को ही देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व लोकसभा का भी रिजल्ट आना था इन्हें पता था कि यदि हम 4 जून को रिजल्ट ओपन करते हैं तो मीडिया इसको बहुत ज्यादा कवरेज नहीं देगा . क्योंकि सारी मीडिया लोकसभा के रिजल्ट के ऊपर कवरेज करने में व्यस्त रहेगी. कुछ लोग कहते हैं जो इसकी जानकारी रखते हैं कि दरअसल 4 जून को आनन फानन में रिजल्ट इसलिए घोषित किया गया क्योंकि कोर्ट में इसके ऊपर पहले से एक क्कुरु लगी हुई थी . एग्जाम के बाद जब यह खबर आई थी कि पेपर लीक हो गया है तो कोर्ट में केस लगाया गया था. लेकिन तब कोर्ट ने एग्जाम कैंसिल करने के बात को मना कर दिया था और अगली सुनवाई के लिए कहा था कि वेकेशन के बाद जब कोर्ट में स्टार्ट होगा तो सुनवाई होगी, इस पर एक छात्रा ने 4 जून को सुबह ही सुप्रीम कोर्ट पर एक PIL दायर करती हैं और जैसी वह PIL दायर करते हैं इधर शाम को 4.00 बजे नीट अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट घोषित कर देता है . बताते हैं कि अक्सर जो रिजल्ट देर शाम को घोषित होता था उस नीट ने नीट फिर शाम को 4:00 बजे क्यों घोषित किया.

आखिर रिजल्ट घोषित करने की तारीख 4 जून चुनने की क्या आवश्यकता पड़ी . दाल में कुछ काला होने की शंका तो यहाँ से उत्पन्न करती है. (**शेष पृष्ठ 2 पर**)

धर्मेन्द्र प्रधान ने माना एनटीए में सुधार जरुरी

नीट परीक्षा परिणाम में धांधली को लेकर देशभर में छात्र और अभिभावक एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. 2024 का नीट एग्जाम दे चुके उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद भी परेशान हैं। वे परीक्षा में हुई अनियमितता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देशभर के भावी डॉक्टर भीषण गर्मी में सड़कों पर न्याय की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। देशभर में आन्दोलन हो रहे हैं। NSUI, AISA, SFI और ABVP छत्र संगठनों के साथ मिलकर ये लोग जमकर आवाज उठा रहे हैं. उधर, बिहार के पटना–नालंदा और गुजरात के गोधरा में नीट पेपर लीक की ओर संकेत करने वाले कई सबूत मिले हैं, गिफ्तारियां हो रही हैं. बिहार में पकड़े गए कई आरोपियों ने EOU की पूछताछ में पेपर लीक और एजेंसी के अधिकारियों से सांठगांठ की बात कबूल की है. इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अब यूटर्न नजर आ रहा है. मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि NEET के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था का विषय सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी थी कि कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनको ग्रेस नंबर दिए गए। दूसरा 2 जगहों पर कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। मैं छात्रो और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। जानकारी हमें मिली है, हम सारे विषयों को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें जो भी बड़े अधिकारी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। NTA में बहुत सुधार की आवश्यकता है। सरकार इस पर चिंता कर रही है, किसी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा।

धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान तब आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मॉर्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया है। यह परीक्षा 23 जून को होगी। इसके नतीजे 30 जून तक आएंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले भी नीट के पेपर लीक होने का हवाला देते हुए इसके रिजल ?ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब भी नीट के रिजल ?ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

बीते शनिवार धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ छात्रों और अभिभावकों से अपने दफ्तर में मुलाकात की थी. उन्होने बताया था कि जो छात्र हमसे मिलना चाहते थे, मैंने उनका पक्ष सुना और मैंने उन्हें बेहतर महसूस कराया. सरकार प्रतिबद्ध है, और सभी छात्रों को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.

मैनेजर ने लिया मालिक का बदला

जिस स्मृति ईरानी ने साल 2019 में राहुल गांधी जैसे नाम चीन नेता को गांधी -नेहरु परिवार की सुरक्षित सीट अमेठी से 55 हजार मतों से हरा दिया था, वही स्मृति ईरानी पांच सालों में 1 लाख 60 हजार से अधिक मतों से चुनाव कैसे हार गईं. यहां तक कि बीजेपी के दो विधायक, राज्य मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष के इलाके में भी स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा.

केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी की अमेठी से प्रत्याशी स्मृति ईरानी की हार की चर्चा राजनीतिक गलियारे में खूब हो रही है चर्चा है कि जिस स्मृति ईरानी ने साल 2019 में राहुल गांधी जैसे नाम चीन नेता को गांधी – नेहरु परिवार की सुरक्षित सीट अमेठी से 55 हजार मतों से हरा दिया था, वही स्मृति ईरानी पांच सालों में 1 लाख 60 हजार से अधिक मतों से चुनाव कैसे हार गईं. यहां तक कि बीजेपी के दो विधायक, राज्य मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष के इलाके में भी स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा. दरअसल दूसरे बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की तरह स्मृति को यह लगा था कि राम मंदिर की सीढ़ियों से चुनाव जीतने का दोतिहाई रास्ता तो तय हो गया है, बाकी एक तिहाई का काम अमेठी में उनका गृहप्रवेश कर देगा . याद है न आपको 22 फरवरी के दिन जब स्मृति ईरानी ने अमेठी के अपने घर का गृहप्रवेश करा था. माथे पर कलश लेकर पारसी पति जुबिन ईरानी के साथ अपने नए घर में कदम रखा. उज्जैन से आए पंडितों ने पूरे विधिविधान के साथ हवनपूजन कराया था. उन दिनों स्मृति ईरानी को शायद यह महूसस हुआ हो कि अमेठी की जनता के दिल में उतरने के लिए यह सबसे बेहतर तरीका है लेकिन चुनाव के नतीजों ने उनकी सोशल इंजीनियरिंग की पोल खोल दी. हालांकि किशोरी लाल शर्मा से चारों खाने चित होने के बाद भी स्मृति की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, नतीजे आने के बाद हुए प्रेस कौन्फ्रेंस के दौरान स्मृति ने कहा कि उनका जोश अभी भी हाई है, स्मृति का यही एटीट्यूड असल में उनको ले डूबा. साल 2023 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में वे एक पत्रकार के ऊपर जबरदस्त भड़क गई थीं, पत्रकार विपिन यादव का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने केंद्रीय मंत्री से एक बाइट मांगी थी, इस पर स्मृति ने कहा था, अगर आप मेरे क्षेत्र का अपनाम करेंगे, तो मैं आपके मालिक से फोन करके कहूंगी. इसके बाद उस पत्रकार की नौकरी चली गई थी. कई ऐसे मौके थे जब स्मृति ईरानी के बात करने के तरीके पर सवाल उठा. राहुल गांधी पर उनका तंज कम होने का नाम नहीं ले रहा था, यूपी में सातवें चरण के लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले वाराणसी में एक चुनावी रैली के दौरान स्मृति ईरानी का माइक खराब हो जाता है, इस पर चुटकी लेते हुए वह कहती हैं, माइक वाले का नाम राहुल तो नही उनके इस कमेंट की काफी आलोचना हुई थी लोगों ने कहा था कि एक केंद्रीय मंत्री की तरफ से ऐसा बयान दिया जाना काफी निराशाजनक है. प्रियंका गांधी पर किया गया उनका तंज भी बहुत चर्चा में रहा, इसमें वह प्रियंका की मिमिक्री करती दिखी थीं. स्मृति ने कहा था कि राममंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद वे मंदिर जा सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें वोट मिलेगा, यानी वे भगवान को धोखा देने जाएंगे. राहुल पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री मैडम ईरानी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल करते हैं वह हम सबका क्या खाक हो पाएगा, जो सच्चे मन से राम का नहीं वह हमारे किसी काम का नहीं. अब चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद यह कहा जा सकता है कि राम अगर राहुल के काम नहीं आए, तो स्मृति ईरानी के काम भी नहीं आए.

वैसे लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शाम को कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की परंपरा निभाने के लिए भाजपा कार्यालय पहुंचे तो स्वाभाविक तौर पर उन का चेहरा कुछ उतरा हुआ था , आवाज में पहले जेसा दम नहीं था क्योंकि जो जीत भाजपा के हिस्से में आई है वह शर्मनाक है. पार्टी का 240 सीटों पर सिमट जाना उतना ही अप्रत्याशित था जितना यह कि इस कार्यक्रम में भाषण की शुरुआत ही जय जगन्नाथ से करना था. ओडिशा में मिली कामयाबी के बाबत जगन्नाथ के प्रति आभार और आस्था व्यक्त करने के साथसाथ उन्हें जय श्रीराम न बोलने का खूबसूरत बहाना भी मिल गया. कट्टर हिंदूवादी तो बौखलाएगे ही क्योंकि ये नतीजे उन की दुकान, मंशा और मिशन पर पानी फेरते हुए आया हैं. अधिकतर लोग ऐसे भी है जो यह राग अलापते नजर आ रहे हैं कि अच्छा हुआ जो भाजपा और मोदी को बेलगाम होने का मौका नहीं मिला. क्योंकि अब काफी हद तक फैसला अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता के सहमती से होगा. अपाहिज भाजपा इन 2 बैसाखियों के सहारे ही चलेगी, क्योंकि वह कोई रिस्क नहीं उठाएगी. अब जो भी हो लेकिन यूपी के 2 लड़कों ने भाजपाई मंसूबों पर ग्रहण तो लगा ही दिया है. यह झटका जोरो का है और लगा भी जोर से है . जिस ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर केवल हिंदुत्व के नाम पर क्या मिल रहा है एक तबका और भी है जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है लेकिन हिंदुत्व के चलते खामोश था. चुनाव परिणामों का यह रुख तय करेगा कि भविष्य की राजनीति का मिजाज कैसा होगा ....

बिना अनुमति अधिकारी/कर्मचारी मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों से अब नहीं मिल पाएंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के शासकीय सेवकों को अपनी निजी समस्या के कारण मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिए उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त करना होगा। यदि कोई शासकीय सेवक विभागीय चैनल की अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होता है तो इस प्रकार की उपस्थिति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 21 के अंतर्गत कदाचरण मानी जाएगी और संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी इस आशय से संबंधित परिपत्र में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने जारी किया है। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों एवं अन्य सेवाओं से संबंधित मामलों के निराकरण हेतु उचित माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश पूर्व से ही दिए गए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के बावजूद यह देखा जा रहा है कि शासकीय सेवकों द्वारा सीधे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष बिना विभागीय अनुमति प्राप्त किये उपस्थित हो रहे हैं। इस प्रकार की कार्य प्रणाली से न सिर्फ कर्मचारियों का अनुशासन प्रभावित होता है, बल्कि संबंधित कर्मचारी का भी समय व्यर्थ नष्ट होता है जिसके कारण उनके कार्यस्थल की सेवा भी प्रभावित होती है।

मुख्यमंत्री साय दिखे किसान की भूमिका में

बगिया में अपने खेतों में बीज का छिड़काव कर खेती-किसानी का किया शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ राज्य की कमान संभालने के साथ साथ अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी संभाल रहे हैं। उन्होंने अपने गृह ग्राम बगिया में मानसून की आहट को देखते हुए पुश्तैनी खेतों में खेती–किसानी की शुरूआत की। उन्होंने स्वयं एक किसान की तरह धान की बोनी कर परंपरा का निर्वहन किया।

मुख्यमंत्री ने परंपरा के मुताबिक पांच बार बीजों को अपने हाथों में लेकर खेतों में बिखरा दिया, इसके बाद परिवारजनों ने भी उनका अनुसरण किया। खेती–किसानी को लेकर जशपुर, सरगुजा अंचल के किसानों में ऐसी परंपरा है, जिसमें परिवार के लोग मुखिया के साथ धान की बोनी की रस्म निभाते हैं।

मुख्यमंत्री खेती–किसानी का पारंपरिक परिधान पहनकर खेतों में नजर आए। उन्होंने पगड़ी लगाई और पारंपरिक वस्त्र पहना इसके बाद टोकरी में धान बीज रखे और इनकी पूजा की गई।

उल्लेखनीय है कि फसल की समृद्धि की कामना के लिए बीज छिड़कने के पूर्व यह रस्म जशपुर–सरगुजा क्षेत्र में की जाती है। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है प्रदेश का हर किसान खेती किसानी की तैयारियों में जुट गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश में बेहतर खरीफ फसल के लिए बीते दिनों कृषि विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी की।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा आसमां पब्लिशर्स इंडिया प्रा.लि. जयराम काम्पलेक्स गली, मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, सांई वाटिका,जोरातालाब के पास रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979